सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 129, नई दिल्ली । शनिवार, 20 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी।

03 दिल्ली में फेल होने वाले बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है : सचदेवा
06 संसद नई, परंतु शासन पुराना
08 वायुसेना उपप्रमुख बोले- भारत में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देने की जरूरत

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए काम की खबर

दो दिनों के लिए हुआ टाइमिंग में बदलाव, जानें वजह

दिल्ली मेट्रो ने येलो लाइन पर शनिवार और रविवार दो दिन के लिए मेट्रो परिचालन के समय में बदलाव किया है। इससे येलो लाइन पर शनिवार की रात मेट्रो का परिचालन जल्दी बंद हो जाएगा। वहीं रविवार सुबह समयपुर बादली से जहांगीरपुरी के बीच एक घंटे की देरी से मेट्रो उपलब्ध हो जाएगी। दरअसल हैदरपुर बादली मोड के पास 490 मीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर का काम चल रहा है।

संजय बाटला

नई दिल्ली। फेज चार में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो लाइन का कॉरिडोर वर्तमान येलो लाइन के हैदरपुर बादली मोड स्टेशन के ऊपर से गुजरेगा। इसके लिए हैदरपुर बादली मोड के पास 490 मीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर का काम चल रहा है।

इसके मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने येलो लाइन पर शनिवार और रविवार दो दिन के लिए मेट्रो परिचालन के समय में बदलाव किया है। इससे येलो लाइन पर शनिवार की रात मेट्रो का परिचालन जल्दी बंद हो जाएगा। वहीं रविवार सुबह समयपुर बादली से जहांगीरपुरी के बीच एक घंटे की देरी से मेट्रो उपलब्ध हो जाएगी।

शनिवार को अंतिम ट्रेन रात 10.45 बजे होगी उपलब्ध

डीएमआरसी का कहना है कि फेज चार के कॉरिडोर के निर्माण कार्य के कारण येलो लाइन की मेट्रो में यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके मद्देनजर हैदरपुर बादली मोड़ के पास रात के वक्त जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर का काम होगा। इस वजह से शनिवार को येलो लाइन पर समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के लिए अंतिम ट्रेन रात 11 बजे की जगह रात 10:45 बजे उपलब्ध होगी।

बादली के लिए अंतिम ट्रेन 9.30 बजे तक ही मिलेगी

वहीं मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से समयपुर बादली के लिए अंतिम ट्रेन रात 11 बजे की जगह रात 9:30 बजे उपलब्ध होगी। रविवार को समयपुर बादली से गुरुग्राम के लिए पहली मेट्रो सुबह सात बजे उपलब्ध होगी। जबकि सामान्य दिनों में सुबह छह बजे उपलब्ध होती है। लेकिन जहांगीरपुरी से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के बीच परिचालन सामान्य रूप से होगा।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्लीवालों के गुड न्यूज! खुलने वाला है मेट्रो के फेज-4 का पहला सेक्शन, जानिए कहां से कहां तक जा सकेंगे

दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तहत मजेंटा लाइन का विस्तार जनकपुरी वेस्ट से रामकृष्ण आश्रम मार्ग तक किया जा रहा है। इसका पहला सेक्शन, जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन (2.2 किमी, अंडरग्राउंड), अगले महीने खुलने की उम्मीद है। यात्रियों को जनकपुरी वेस्ट पर ट्रेन बदलनी होगी। पूरा कॉरिडोर 29.26 किमी लंबा होगा और इसमें 22 नए स्टेशन होंगे।

नई दिल्ली : मेट्रो के फेज-4 का पहला सेक्शन जल्द ही यात्रियों की आवाजाही के लिए खुलने वाला है। नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से दिल्ली के जनकपुरी वेस्ट के बीच फेज-3 में बनी मेट्रो की मजेंटा लाइन को फेज-4 में जनकपुरी वेस्ट से आगे रामकृष्ण आश्रम मार्ग तक एक्सटेंड किया जा रहा है। इसी लाइन के एक छोटे से हिस्से को जल्द ही यात्रियों के लिए खोलने की तैयारी है। इसके तहत जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू किया जाएगा, जो फेज-4 का पहला सेक्शन होगा। इसी के साथ मेट्रो के ऑपरेशनल नेटवर्क में एक और नया स्टेशन भी जुड़ जाएगा।

अंडरग्राउंड होगा 2.2 किमी का ये एक्टेंशन

जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन की दूरी महज 2.2 किमी होगी। यह पूरा सेक्शन अंडरग्राउंड होगा, लेकिन जनकपुरी से कृष्णा पार्क जाने के लिए यात्रियों को ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक, अभी जनकपुरी वेस्ट मजेंटा लाइन का टर्मिनल स्टेशन है। इस अंडरग्राउंड स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जिनसे अभी बॉटनिकल गार्डन के लिए ट्रेनें आती-जाती थीं, लेकिन अब उनमें से एक प्लेटफॉर्म को जनकपुरी से आगे कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक जाने के लिए रिजर्व कर दिया गया है, जहां से एक अलग ट्रेन यात्रियों को आगे लेकर जाएगी। बॉटनिकल गार्डन की तरफ से आ रहे जिन यात्रियों को जनकपुरी वेस्ट से आगे कृष्णा पार्क एक्सटेंशन जाना होगा, उन्हें पहले जनकपुरी वेस्ट के प्लैटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन से उतरना होगा और फिर बगल में ही बने प्लैटफॉर्म नंबर 3 से दूसरी ट्रेन में सवार होकर कृष्णा पार्क जाना पड़ेगा। यह सिस्टम ठीक वैसा ही होगा, जैसा मेट्रो की पिंक लाइन पर मौजपुर से शिव विहार जाने के लिए बनाया गया है, जिसमें पिंक लाइन की ट्रेन से आ रहे यात्रियों को मौजपुर-बाबरपुर से दूसरी ट्रेन में सवार होकर आगे जाना पड़ता है।

कृष्णा पार्क से आगे मेट्रो लाइन एलिवेटेड हो जाएगी

मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि कृष्णा पार्क से आगे मेट्रो लाइन एलिवेटेड हो जाएगी। इसके लिए यहां जो रैंप बनाया गया है, वहीं से ट्रेन रिवर्स होकर वापस जनकपुरी आएगी। चूंकि रिवर्सल में समय ज्यादा लगता है, इसलिए बाकी की लाइन पर ट्रेन ऑपरेशन प्रभावित ना हो, इसीलिए अभी यह सिस्टम बनाया गया है, जिसमें जनकपुरी से आगे जाने के लिए यात्रियों को दूसरी ट्रेन में सवार होना पड़ेगा। वहीं, जो ट्रेन बॉटनिकल गार्डन से आकर जनकपुरी वेस्ट पर टर्मिनेट होगी, वो उसी प्लैटफॉर्म से वापस चली जाएगी। इससे ट्रेनों का शेड्यूल ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो के नए सेक्शन पर लगाए गए सभी सिस्टम की जांच चल रही है। जल्द ही मेट्रो ट्रेनों के साथ ट्रायल भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) से सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए अनुरोध किया जाएगा। डीएमआरसी को उम्मीद है कि अगले महीने के अंत तक इस सेक्शन को यात्रियों के इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाएगा।

22 नए मेट्रो स्टेशंस होंगे

मेट्रो की मजेंटा लाइन का एक्सटेंशन फेज-4 की तीन लाइनों में सबसे लंबा होगा। इसके तहत जनकपुरी वेस्ट से रामकृष्ण आश्रम मार्ग के बीच 29.26 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जिस पर कुल 22 नए मेट्रो स्टेशंस होंगे। इस लाइन का 19.52 किमी लंबा हिस्सा एलिवेटेड और 9.4 किमी लंबा हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इस लाइन के बनने के साथ ही मेट्रो नेटवर्क में 8 नए इंटरचेंज

NCR से दिल्ली की ओर आने वाले ड्राइवर सावधान! कट सकता है 11,000 तक का भारी चालान

परिवहन विशेष न्यूज

HSRP या अनिवार्य ईंधन कलर कोड स्टिकर की नहीं रहने वाले वाहनों पर 11,000 रुपये तक का भारी चालान जारी करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल टीमें तैनात हुई है.

नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम को शामिल करते हुए दिल्ली-एनसीआर कॉरिडोर में यात्रा करने वाले कार-बाइक ड्राइवर सावधान हो जाएं! ड्राइवरों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके वाहन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) से लैस हों. क्योंकि सोमवार से, दिल्ली परिवहन विभाग और ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा इस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

एक बार फिर शुरू हुआ अभियान

इस अभियान को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया था मगर एक बार फिर इस अभियान को अब सख्ती से लागू किया जाएगा. HSRP या अनिवार्य ईंधन कलर कोड स्टिकर की नहीं रहने वाले वाहनों पर 11,000 रुपये तक का भारी चालान जारी करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल टीमें तैनात हुई है.

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्यों?

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माण वाहनों चोरी से बचाने के लिए किया गया था. HSRP में एक Unique laser-engraved identification number और एक होलोग्राम होता है जिसकी मदद से गाड़ी की पूरी जानकारी चंद सेकेंड में पता चल जाती है.

अलग-अलग वाहनों में अलग-अलग रंग के ईंधन कलर कोड स्टिकर होते हैं

अलग-अलग वाहनों में अलग-अलग रंग के ईंधन कलर कोड स्टिकर होते हैं. जहां Petrol और CNG वाहनों के लिए नीले रंग का स्टिकर, डीजल वाहनों के लिए भूरे रंग का और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग का स्टिकर ज़रूरी होता है. HSRP या रंग कोड विनियमों का पालन न करने पर अलग से 5500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

Unique Laser-Engraved Identification Number

HSRP एक मजबूत एंटी-थेफ्ट उपाय है, जो सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है. इसमें एक Unique laser-engraved identification number और एक होलोग्राम होता है. जहां Petrol और CNG वाहनों के लिए नीले रंग का स्टिकर, डीजल वाहनों के लिए भूरे रंग का और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग का स्टिकर ज़रूरी होता है. HSRP या रंग कोड विनियमों का पालन न करने पर अलग से 5500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

अपनी गाड़ी से दफ्तर नहीं आएं दिल्ली सचिवालय के कर्मचारी, स्पेशल बस से करें सफर...

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक भीड़भाड़ को कम करने और बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच दिल्ली सरकार ने आईपी मेट्रो स्टेशन से सचिवालय तक अपने कर्मचारियों के लिए बस सेवा शुरू की है. ताकि वे निजी वाहनों का इस्तेमाल करना बंद कर दें. बस का किराया भी नॉर्मल एसी बस सर्विस का ही लागू रहेगा.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने और सफर को इको फ्रेंडली बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डीटीसी की तरफ से एक नए स्पेशल बस रूट की शुरुआत की गई है, जो कर्मचारियों को आईपी मेट्रो स्टेशन से दिल्ली सचिवालय और दिल्ली सचिवालय से आईपी मेट्रो स्टेशन लाने ले जाएगी. नॉर्मल एसी बस सर्विस किराए के साथ चलने वाली यह बसें कर्मचारियों के लिए बेहद सुविधाजनक बताई गई हैं.

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने लिखा था पत्र: दरअसल, जून में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ओर से एक पत्र दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी को लिखा गया था. इसके जरिए नगिम ने सचविालय कर्मचारियों के लिए नई बस सर्विस आईपी मेट्रो स्टेशन और दिल्ली सचिवालय के बीच दोनों दिशाओं में चलाने को लेकर अवगत कराया. डीटीसी ने जीएडी से आग्रह किया था कि कर्मचारियों की सुविधा और दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक भीड़भाड़ को कम करने और स्टाफ के लिए सफर को इको फ्रेंडली बनाने के मद्देनजर बस सेवा शुरू की जा रही है, जिसका किराया नॉर्मल एसी बस सर्विस का ही लागू रहेगा. इस बाबत डीटीसी की तरफ से पूरा रूट प्लान पूरे टाइम टेबल के साथ वभिाग को भेजा गया था.

इस पत्र पर जीएडी की तरफ से भी एक सर्कुलर जारी किया गया, जसिके बाद सामान्य प्रशासनिक विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी की तरफ से एक विभागीय आदेश भी जारी कफिए गए. इसके बाद जीएडी के डप्टिी सेक्रेटरी प्रदीप तायल की ओर से एक सर्कुलर 5 जून को जारी किया गया. इसको दिल्ली सरकार के सभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज और विभागों के प्रमुख और दिल्ली सचिवालय में स्थित कार्यालयों को भेजा गया. इस सर्कुलर के माध्यम से सभी विभागों को अवगत कराया गया कि डीटीसी की तरफ से जो बस सेवा शुरू की जा रही है, उसको सचिवालय में स्थित विभागों और कर्मचारियों की तरफ से ज्यादा से ज्यादा सेवा में लिया जाए, जिससे इस सुविधा की शुरुआत करने का खास मकसद हल हो सके.

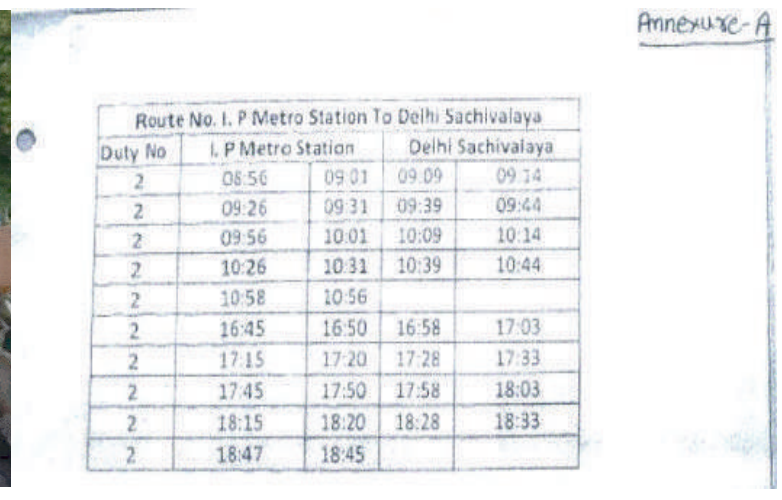

Annexure-A

Route No. I. P Metro Station To Delhi Sachivalaya				
Duty No	I. P Metro Station		Delhi Sachivalaya	
2	08:56	09:01	09:09	09:14
2	09:26	09:31	09:39	09:44
2	09:56	10:01	10:09	10:14
2	10:26	10:31	10:39	10:44
2	10:58	10:56		
2	16:45	16:50	16:58	17:03
2	17:15	17:20	17:28	17:33
2	17:45	17:50	17:58	18:03
2	18:15	18:20	18:28	18:33
2	18:47	18:45		

दिल्लीसच विालयमेंपार्क गिस्पेसकम: सूत्र बताते हैं कि दिल्ली सचिवालय में आने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए यहां वाहन पार्किंग की इतनी बड़ी सुविधा नहीं है जितनी संख्या में हर रोज वाहन यहां पहुंचते हैं. इसकी वजह से दिल्ली सचिवालय के सामने बनी पार्किंग के अलावा उसके बाहर सड़क पर काफी दूर तक दोनों दशिाओं में रोड साइड वाहन खड़े किए जाते हैं. इससे कुछ असुविधा भी सामने आई हैं. वहीं, इस बस सेवा को शुरू करने से पहले जीएडी की तरफ से कर्मचारियों को ऑफिस समय से आने जाने की टाइमगिं भी सुनिश्चित करने की दशिा में कदम उठा चुका है. इस लिहाज से अब यह बस सुविधा काफी अहम भी मानी जा रही है.

पहलेसेकर्मचार यिोंकीटाइम गिपरसख्तहै जीएडी: एक कर्मचारी ने बताया क बिस सुवधिा के शुरू होने से कर्मचारी पर्सनल वाहन से आने की बजाय सार्वजनकि बस सेवा से आना-जाना करेंगे. वह समय से ही ऑफिस छोड़ेंगे. इससे सचिवालय समय से पहले छोड़ने वाले कर्मचारियों की जल्दी जाने और लेट आने की आदत भी छूट जाएगी. उधर, सामान्य प्रशासन विभाग पहले ही कर्मचारियों की आने जाने की ऑफिस टाइमिंग को सुनिश्चित करने को लेकर सख्त रूख अख्तियार किए हुए हैं.

क्या है पूरा रूट और टाइम गि: आईपी मेट्रो स्टेशन से दिल्ली सचिवालय की कुल दूरी 2 किलोमीटर और दिल्ली सचिवालय से आईपी मेट्रो स्टेशन की कुल दूरी 4 किलोमीटर बताई गई है. इस सफर के लिए डीटीसी ने नॉर्मल एसी बस सर्विस फेयर को ही लागू किया है. दोनों दिशाओं में यह बस रूट सुबह आईपी मेट्रो स्टेशन से 8:56 बजे से संचालति होती है, जो करीब 5 मिनट तक पैसेंजर का इंतजार करेगी और 5 मिनट के भीतर यानी सुबह 9:09 बजे पर दिल्ली सचिवालय पहुंचा देगी. इसके बाद सुबह 9:14 पर वहां से वापसी करेगी यानी सुबह के वक्त 10:58 बजे के बाद यह बस सेवा नहीं मिलेगी. शाम के वक्त इसकी शुरुआत 4:45 बजे से होगी और आखिरी बस सेवा 6:45 बजे की होगी।

भारत में महिलाएं

सती प्रथा एक प्राचीन और काफ़ी हद तक विलुप्त रिवाज है, कुछ समुदायों में विधवा को अपने पति की चिता में अपनी जीवित आहुति देनी पड़ती थी। हालांकि यह कृत्य विधवा की ओर से स्वैच्छिक रूप से किये जाने की उम्मीद की जाती थी, ऐसा माना जाता है कि कई बार इसके लिये विधवा को मजबूर किया जाता था। 1829 में अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया। आजादी के बाद से सती होने के लगभग चालीस मामले प्रकाश में आये हैं।

> कुछ समुदायों में सती, जौहर और देवदासी जैसी परंपराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और आधुनिक भारत में ये काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। हालांकि इन प्रथाओं के कुछ मामले भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी देखे जाते हैं। कुछ समुदायों में भारतीय महिलाओं द्वारा परदा प्रथा को आज भी जीवित रखा गया है....

भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।

इतिहास

विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका की चर्चा करने वाले साहित्य के स्रोत बहुत ही कम हैं; 1730 ई. के आसपास तंजावुर के एक अधिकारी त्र्यम्बकयज्वन का स्त्रीधर्मपद्धति इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। इस पुस्तक में प्राचीन काल के अपस्तंभ सूत्र (चौथी शताब्दी ई.पू.) के काल के नारी सुलभ आचरण संबंधी नियमों को संकलित किया गया है।[5] इसका मुखड़ा छंद इस प्रकार है:
मुख्यो धर्मः स्मृतिषु विहितो भार्तृशुश्रुषानम हि :
स्त्री का मुख्य कर्तव्य उसके पति की सेवा से जुडा हुआ है।
जहाँ सुश्रूषा शब्द (अर्थात, "सुनने की चाह") में ईश्वर के प्रति भक्त की प्रार्थना से लेकर एक दास की निष्ठापूर्ण सेवा तक कई तरह के अर्थ समाहित हैं।[6]

प्राचीन भारत

विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था।[7] हालांकि कुछ अन्य विद्वानों का नजरिया इसके विपरीत है।[8] पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि प्रारम्भिक वैदिक काल[9][10] में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेदिक ऋचाएं यह बताती हैं कि महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी और संभवतः उन्हें अपना पति चुनने की भी आजादी थी।[11] ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और संतों के बारे में बताते हैं जिनमें गार्गी और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय हैं।[12]
प्राचीन भारत के कुछ साम्राज्यों में नगरवधु ("नगर की दुल्हन") जैसी परंपराएं मौजूद थीं। महिलाओं में नगरवधु के प्रतिष्ठित सम्मान के लिये प्रतियोगिता होती थी। आम्रपाली नगरवधु का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण रही है।
अध्ययनों के अनुसार प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को बराबरी का दर्जा और अधिकार मिलता था।[13] हालांकि बाद में (लगभग 500 ईसा पूर्व में) स्मृतियों (विशेषकर मनुस्मृति) के साथ महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरु हो गयी और बाबर एवं मुगल साम्राज्य के इस्लामी आक्रमण के साथ और इसके बाद ईसाइयत ने महिलाओं की आजादी और अधिकारों को सीमित कर दिया।[4]
हालांकि जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलनों में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति दी गयी है, भारत में महिलाओं को कमोबेश दासता और बंदिशों का ही सामना करना पड़ा है।[13] माना जाता है कि बाल विवाह की प्रथा छठी शताब्दी के आसपास शुरु हुई थी।[14]

मध्ययुगीन काल

समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आयी[4][7] जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक, सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा बन गयी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने परदा प्रथा को भारतीय समाज में ला दिया। राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियां या मंदिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था। बहुविवाह की प्रथा हिन्दू क्षत्रिय शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी।[14] कई मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को जनाना क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था।
इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की। [4] रज़िया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सम्राज्ञी बनीं। गोंड की महारानी दुर्गावती ने 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ़ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले पंद्रह वर्षों तक शासन किया था। चांद बीबी ने 1590 के दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ़ अहमदनगर की रक्षा की। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में पहचान हासिल की। मुगल राजकुमारी जहाँआरा और जेबुन्निसा सुप्रसिद्ध कवियित्रियाँ थीं और उन्होंने सत्तारूढ़ प्रशासन को भी प्रभावित किया। शिवाजी की माँ जीजाबाई को एक योद्धा और एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण क्वीन रीजेंट के रूप में पदस्थापित किया गया था। दक्षिण भारत में कई महिलाओं ने गाँवों, शहरों और जिलों पर शासन किया और सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों की शुरुआत की।[14]
भक्ति आंदोलन ने महिलाओं की बेहतर स्थिति को वापस हासिल करने की कोशिश की और प्रभुत्व के स्वरूपों पर सवाल उठाया।[13] एक महिला संत-कवयित्री मीराबाई भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थीं। इस अवधि की कुछ अन्य संत-कवयित्रियों में अक्का महादेवी, रामी जानाबाई और लाल देद शामिल हैं। हिंदुत्व के अंदर महानुभाव, वरकारी और कई अन्य जैसे भक्ति संप्रदाय, हिंदू समुदाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक न्याय और समानता की खुले तौर पर वकालत करने वाले प्रमुख आंदोलन थे।
भक्ति आंदोलन के कुछ ही समय बाद सिक्खों के पहले गुरु, गुरु नानक ने भी पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के संदेश को प्रचारित किया। उन्होंने महिलाओं को धार्मिक संस्थानों का नेतृत्व करने; सामूहिक प्रार्थना के रूप में गाये जाने वाले वाले कीर्तन या भजन को गाने और इनकी अगुआई करने; धार्मिक प्रबंधन समितियों के सदस्य बनने; युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने; विवाह में बराबरी का हक और अमृत (दीक्षा) में समानता की अनुमति देने की वकालत की। अन्य सिख गुरुओं ने भी महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ उपदेश दिए।

ऐतिहासिक प्रथाएं

कुछ समुदायों में सती, जौहर और देवदासी जैसी परंपराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और आधुनिक भारत में ये काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। हालांकि इन प्रथाओं के कुछ मामले भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी देखे जाते हैं। कुछ समुदायों में भारतीय महिलाओं द्वारा परदा प्रथा को आज भी जीवित रखा गया है और विशेषकर भारत के वर्तमान कानून के तहत एक गैरकानूनी कृत्य होने के बावजूद बाल विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है।

सती

सती प्रथा एक प्राचीन और काफ़ी हद तक विलुप्त रिवाज है, कुछ समुदायों में विधवा को अपने पति की चिता में अपनी जीवित आहुति देनी पड़ती थी। हालांकि यह कृत्य विधवा की ओर से स्वैच्छिक रूप से किये जाने की उम्मीद की जाती थी, ऐसा माना जाता है कि कई बार इसके लिये विधवा को मजबूर किया जाता था। 1829 में अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया। आजादी के बाद से सती होने के लगभग चालीस मामले प्रकाश में आये हैं।[15] 1987 में राजस्थान की रूपकंवर का मामला सती प्रथा (रोक) अधिनियम का कारण बना।[16]

जौहर

जौहर का मतलब सभी हारे हुए (सिर्फ राजपूत) योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों के शत्रु द्वारा बंदी बनाये जाने और इसके बाद उत्पीड़न से बचने के लिये स्वैच्छिक रूप से अपनी आहुति देने की प्रथा है। अपने सम्मान के लिए मर-मिटने वाले पराजित राजपूत शासकों की पत्नियों द्वारा इस प्रथा का पालन किया जाता था। यह कुप्रथा केवल भारतीय राजपूतों शासक वर्ग तक सीमित थी प्रारंभ में और राजपूतों ने या शायद एक-आध किसी दूसरी जाति की स्त्री ने सति (पति/पिता की मृत्यु होने पर उसकी चिता में जीवित जल जाना) जिसे उस समय के समाज का एक वर्ग पुनीत धार्मिक कार्य मानने लगा था। कभी भी भारत की दूसरी लडाका कोमो या जिन्हे ईन्गलिश में रमार्शल कौमेस माना गया उनमें यह कुप्रथा कभी भी कोई स्थान न पा सकी। गुर्जरों व जाटों की स्त्रीयां युद्ध क्षेत्र में पति के कन्धे से कन्धा मिला दुश्मनों के दान्त खट्टे करते हुए शहीद हो जाती थी। मराठा महिलाएँ भी अपने योधा पति की युधभूमि में पूरा साथ देती रही हैं।

परदा

परदा वह प्रथा है जिसमें कुछ समुदायों में महिलाओं को अपने तन को इस प्रकार से ढंकना जरूरी होता है कि उनकी त्वचा और रूप-रंग का किसी को अंदाजा ना लगे।

देवदासी

देवदासी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में एक धार्मिक प्रथा है जिसमें देवता या मंदिर के साथ महिलाओं की "शादी" कर दी जाती है। यह परंपरा दसवीं सदी ए.डी. तक अच्छी तरह अपनी पैठ जमा जुकी थी।[17] बाद की अवधि में देवदासियों का अवैध यौन उत्पीडन भारत के कुछ हिस्सों में एक रिवाज बन गया।

अंग्रेजी शासन

यूरोपीय विद्वानों ने 19वीं सदी में यह महसूस किया था कि हिंदू महिलाएं "स्वाभाविक रूप से मासूम" और अन्य महिलाओं से "अधिक सच्चरित्र" होती हैं।[18] अंग्रेजी शासन के दौरान राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, आदि जैसे कई सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिये लड़ाइयाँ लड़ीं. हालांकि इस सूची से यह पता चलता है कि राज युग में अंग्रेजों का कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं था, यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि मिशनरियों की पत्नियाँ जैसे कि मार्था मौल्ट नी मीड और उनकी बेटी एलिज़ा काल्डवेल नी मौल्ट को दक्षिण भारत में लडकियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये आज भी याद किया जाता है – यह एक ऐसा प्रयास था जिसकी शुरुआत में स्थानीय स्तर पर रुकावटों का सामना करना पड़ा क्योंकि इसे परंपरा के रूप में अपनाया गया था। 1829 में गवर्नर-जनरल विलियम केवेंडिश-बेंटिक के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयास सती प्रथा के उन्मूलन का कारण बने। विधवाओं की स्थिति को सुधारने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संघर्ष का परिणाम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के रूप में सामने आया। कई महिला सुधारकों जैसे कि पंडिता रमाबाई ने भी महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद की।
कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी, कित्तूर चेन्नम्मा ने समाप्ति के सिद्धांत (डाक्ट्रिन ऑफ़ लैप्स) की प्रतिक्रिया में अंग्रेजों के खिलाफ़ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। तटीय कर्नाटक की महारानी अब्बक्का रानी ने 16वीं सदी में हमलावर यूरोपीय सेनाओं, उल्लेखनीय रूप से पुर्तगाली सेना के खिलाफ़ सुरक्षा का नेतृत्व किया। झाँसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ़ 1857 के भारतीय विद्रोह का झंडा बुलंद किया। आज उन्हें सर्वत्र एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में माना जाता है। अवध की सह-शासिका बेगम हज़रत महल एक अन्य शासिका थी जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सौदेबाजी से इनकार कर दिया और बाद में नेपाल चली गयीं। भोपाल की बेगमें भी इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय महिला शासिकाओं में शामिल थीं। उन्होंने परदा प्रथा को नहीं अपनाया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया।
चंद्रमुखी बसु, कादंबिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी कुछ शुरुआती भारतीय महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियाँ हासिल कीं। 1917 में महिलाओं के पहले प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की माँग के लिये विदेश सचिव से मुलाक़ात की जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था। 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया था।[13] 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार एक लड़की के लिये शादी की न्यूनतम उम्र चौदह वर्ष निर्धारित की गयी थी।[13][19] हालांकि महात्मा गाँधी ने स्वयं तेरह वर्ष की उम्र में शादी की, बाद में उन्होंने लोगों से बाल विवाहों का बहिष्कार करने का आह्वान किया और युवाओं से बाल विधवाओं के साथ शादी करने की अपील की।[20]
भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। भिकाजी कामा, डॉ॰ एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरुना आसफ़ अली, सुचेता कृपलानी और कस्तूरबा गाँधी कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय नाम हैं मुथुलक्ष्मी रेड्डी, दुर्गाबाई देशमुख आदि। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की झाँसी की रानी रेजीमेंट कैप्टेन लक्ष्मी सहगल सहित पूरी तरह से महिलाओं की सेना थी। एक कवियित्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला और भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं।

स्वतंत्र भारत इंदिरा गांधी

भारत में महिलाएं अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं।[4] इंदिरा गांधी जिन्होंने कुल मिलाकर पंद्रह वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री हैं।[21]
भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को सामान अधिकार (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15 (1)), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 15(3)), महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने (अनुच्छेद 51(ए)(ई)) और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है। (अनुच्छेद 42)].[22]
भारत में नारीवादी सक्रियता ने 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध के दौरान रफ़्तार पकड़ी. महिलाओं के संगठनों को एक साथ लाने वाले पहले राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में से एक मथुरा बलात्कार का मामला था। एक थाने (पुलिस स्टेशन) में मथुरा नामक युवती के साथ बलात्कार के आरोपी पुलिसकर्मियों के बरी होने की घटना 1979-1980 में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का कारण बनी। विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया और सरकार को साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को संशोधित करने और हिरासत में बलात्कार की श्रेणी को शामिल करने के लिए मजबूर किया गया।[22] महिला कार्यकर्ताएं कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद, महिला स्वास्थ्य और महिला साक्षरता जैसे मुद्दों पर एकजुट हुईं.

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल

चूंकि शराब की लत को भारत में अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जोड़ा जाता है,[23] महिलाओं के कई संगठनों ने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में शराब-विरोधी अभियानों की शुरुआत की।[22] कई भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने शरीयत कानून के तहत महिला अधिकारों के बारे में रूढ़िवादी नेताओं की व्याख्या पर सवाल खड़े किये और तीन तलाक की व्यवस्था की आलोचना की।[13]
1990 के दशक में विदेशी दाता एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों ने नई महिला-उन्मुख गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) के गठन को संभव बनाया। स्वयं-सहायता समूहों एवं सेल्फ इम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन (सेवा) जैसे एनजीओ ने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कई महिलाएं स्थानीय आंदोलनों की नेताओं के रूप में उभरी हैं। उदाहरण के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर.
भारत सरकार ने 2001 को महिलाओं के सशक्तीकरण (स्वशक्ति) वर्ष के रूप में घोषित किया था।[13] महिलाओं के सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गयी थी।[24]
2006 में बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला इमराना की कहानी मीडिया में प्रचारित की गयी थी। इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने किया था। कुछ मुस्लिम मौलवियों की उन घोषणाओं का जिसमें इमराना को अपने ससुर से शादी कर लेने की बात कही गयी थी, व्यापक रूप से विरोध किया गया और अंततः इमराना के ससुर को 10 साल की कैद की सजा दी गयी। कई महिला संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया।

शेष अगले अंक में...

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेरी फार्म में सरकारी जमीन से हटाई गई झुग्गियां, बुलडोजर से ध्वस्त किए पक्के निर्माण

परिवहन विशेष न्यूज

गाजीपुर डेरी फार्म में पशु अस्पताल के पीछे करीब एक से डेढ़ दशक से लोग अवैध रूप से रह रहे थे। किसी ने झुग्गियां डाल रखी थीं तो किसी ने पक्का निर्माण कर लिया था। इनमें से कुछ लोग तो अवैध डेरी संचालित कर रहे थे। इनकी वजह से डेरी फार्म में गंदगी भी रहती थी। इस हिस्से में लैंडफिल साइट की तरफ दीवार भी नहीं बनी थी।

पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने गाजीपुर डेरी फार्म में पशु अस्पताल के पीछे सरकारी जमीन पर बनी झुग्गियों और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। करीब डेढ़ एकड़ भूमि खाली कराई गई है। यहां पर कुछ लोग अवैध रूप से डेरी भी चला रहे थे, उनको भी हटा दिया गया।

निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन के उपायुक्त अंशुल सिरोही का कहना है कि यह भूमि लैंडफिल साइट से सटी हुई थी, जहां दीवार नहीं थी। इस जगह पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर करीब 700 मीटर लंबी दीवार का निर्माण कराया जाएगा।

अवैध रूप से डेढ़ दशक से चला रहे थे डेरी

पशु अस्पताल के पीछे करीब एक से डेढ़ दशक से लोग अवैध रूप से रह रहे थे। किसी ने झुग्गियां डाल रखी थीं, तो किसी ने पक्का निर्माण कर लिया था। इनमें से कुछ लोग तो अवैध डेरी संचालित कर रहे थे। इनकी वजह से डेरी फार्म में गंदगी भी रहती थी। इस हिस्से में लैंडफिल साइट की तरफ दीवार भी नहीं बनी थी, जिस कारण पशु उसके अंदर तक चले जाते थे।

30 से अधिक झुग्गी और पक्के निर्माण हटाए

पिछले दिनों एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। इसके बाद ही नगर निगम अधिकारी हरकत में आए। शुक्रवार को निगम के दस्ते ने डेरी फार्म में पशु अस्पताल के पीछे कार्रवाई कर 30 से अधिक झुग्गी और पक्के निर्माण हटाए। जो लोग अवैध डेरी चला रहे थे, उनको पशु लेकर जाने की रियायत दे दी।

नहीं थम रहीं आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें, दर्ज हुई एफआईआर; दिल्ली क्राइम ब्रांच ने क्यों लिया एक्शन?

मीडिया की सुर्खियां बनीं IAS Pooja Khedkar की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की है। क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी धोखाधड़ी आईटी और विकलांगता अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने यूपीएससी की शिकायत पर आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी और विकलांगता अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर FIR दर्ज की है। संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा खेडकर पर अपने माता-पिता की गलत जानकारी देने के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

आईपीएस पूजा खेडकर लंबे समय से विवादों में घिरी हुई हैं। पूजा खेडकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों उनकी मां भी विवादों में आई थीं, जब उनके हाथ में पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस घटना के बाद से ही पूजा की मां और पिता दोनों ही फरार चल रहे थे। वहीं, पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। महाड से हिरासत में ली गई मनोरमा खेडकर को पुणे ग्रामीण पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, अब प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट पुणे ने 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी पंकज देशमुख ने बताया था कि आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को महाड से हिरासत में लिया गया है लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को आज सुबह पुणे पुलिस ने कथित तौर पर अवैध बंदूक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया।

'दिल्ली में फेल होने वाले बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है', भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा आरोप

बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राजधानी में बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केजरीवाल सरकार के मंत्री दूसरे राज्यों की बात करते हैं लेकिन दिल्ली पर एक शब्द नहीं बोल रहे। वर्ष 2019 -20 में 42 हजार नौवीं में फेल हुए थे। वर्ष 2020-21 में 31 हजार वर्ष 2021-22 में 28 हजार और वर्ष 2022-23 में 88 हजार बच्चे नौवीं कक्षा में फेल हुए।

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी बच्चों को अंधकार में धकेल रही हैं। उन्हें बताना चाहिए कि नौवीं कक्षा में बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? इस वर्ष एक लाख से अधिक बच्चे नौवीं कक्षा में फेल हुए हैं। इस सच्चाई को छिपाने के लिए आतिशी दिल्ली में शिक्षा क्रांति की बात कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार का मॉडल है। दिल्ली सरकार के प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार है।

प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्ली में बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केजरीवाल सरकार के मंत्री दूसरे राज्यों की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली पर एक शब्द नहीं बोल रहे। वर्ष 2019 -20 में 42 हजार नौवीं में फेल हुए थे। वर्ष 2020-21 में 31 हजार, वर्ष 2021-22 में 28 हजार और वर्ष 2022-23 में 88 हजार बच्चे नौवीं कक्षा में फेल हुए।

17 हजार बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया

वर्ष 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 1.1 लाख हो गई। इनमें से दूसरी बार फेल हुए 17 हजार बच्चों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जगह इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। अब ये बच्चे कहां जाएंगे? स्कूल आने के बाद भी पास नहीं होने वाले बच्चे अब कैसे पढ़ाई करेंगे?

शिक्षकों से नारे लगवाए जाते हैं: सचदेवा

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को अपने कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का साधन बना लिए हैं। आए दिन छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को वहां बुलाया जाता है। उनसे आम आदमी पार्टी के पक्ष में नारे लगवाए जाते हैं। आधे से अधिक शिक्षकों को स्कूलों से पढ़ाने की जगह अन्य काम में लगा दिया गया है। इस कारण स्कूलों में पढाई का स्तर नीचे गिर रहा है।

उन्होंने कहा कि 11वीं कक्षा का भी यही हाल है। वर्ष 2019-20 में 12 हजार बच्चे फेल हुए थे। वर्ष 2023-24 में 11 वीं में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर 52 हजार से अधिक हो गई। दिल्ली सरकार के स्कूलों की यह जमीनी सच्चाई है। इसके विपरीत दिल्ली सरकार के मंत्री विश्व स्तरीय शिक्षा माडल होने का प्रचार करते हैं। यह विश्व स्तरीय शिक्षा माडल नहीं भ्रष्टाचार का मॉडल है।

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का दिल्ली के निजी अस्पतालों में भी दिखा असर, करीब साढ़े चार घंटे प्रभावित रही चिकित्सा व्यवस्था

माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने का असर एम्स सहित दिल्ली के किसी बड़े सरकारी अस्पताल में नहीं दिखा। अधिकतर प्राइवेट अस्पताल में काम के दौरान दिक्कतें आईं। मैक्स हेल्थकेयर के प्रवक्ता ने बताया कि अस्पतालों के कंप्यूटर में क्राउडस्ट्राइक एंटीवायरस एंड प्वाइंट का सॉफ्टवेयर अपलोड है। सुबह करीब 10 बजे से लेकर दोपहर 3 .30 बजे तक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने काम करना बंद कर दिया।

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने का असर एम्स सहित दिल्ली के किसी बड़े सरकारी अस्पताल में नहीं दिखा। इस वजह से एम्स, सफदरजंग, आरएमएल सहित सभी अस्पतालों में सामान्य रूप से कामकाज हुआ। लेकिन निजी क्षेत्र के कई अस्पतालों में करीब साढ़े चार घंटा कंप्यूटर सिस्टम प्रभावित रहा।

इसका असर मरीजों के इलाज और चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ी। इस दौरान अस्पतालों में मैनुअल तरीके से मरीजों के ओपीडी कार्ड और बिल भुगतान की प्रक्रिया की गई। इस वजह से कामकाज की गति धीमी रही। इसका असर मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी।

मैक्स अस्पताल में दिखा असर

मैक्स हेल्थकेयर के प्रवक्ता ने बताया कि अस्पतालों के कंप्यूटर में क्राउडस्ट्राइक एंटीवायरस एंड प्वाइंट का सॉफ्टवेयर अपलोड है। सुबह करीब 10 बजे यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद अस्पताल में मरीजों के इलाज व देखभाल में इस्तेमाल होने वाले कई सॉफ्टवेयर ने काम करना बंद कर दिया।

इस वजह से मरीजों के इलाज से जुड़ी प्रक्रिया मैनुअल तरीके करनी पड़ी। इसके बाद सिस्टम दोबारा शुरू हुआ। तब जाकर नियमित तरीके से चिकित्सा व्यवस्था का संचालन शुरू हो सका। मैक्स के दिल्ली में पांच बड़े अस्पताल हैं। इन सब में इसका असर देखने को मिला। इसके अलावा गंगाराम, फोर्टिस सहित कई अन्य अस्पतालों में भी इसका असर रहा।

गंगाराम अस्पताल में दोपहर 3.30 तक रहा काम प्रभावित

गंगाराम अस्पताल ने बयान जारी कहा कि शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण अस्पताल के कंप्यूटर सिस्टम प्रभावित हुए। इस वजह से चिकित्सा सेवाओं के लिए मैनुअल तरीके से काम लिया गया। दोपहर 3:30 बजे स्थिति सामान्य हुई।

फोर्टिस के प्रवक्ता का कहना है कि डायग्नोस्टिक सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित हुईं। जिसका कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया गया और अस्पताल के कंप्यूटर सिस्टम सामान्य रूप से चलते रहे। अपोलो अस्पताल प्रशासन का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने का अस्पताल पर कोई असर नहीं पड़ा। सामान्य रूप से कामकाज हुआ।

सरकारी अस्पतालों में नहीं हुई कोई दिक्कत

एम्स का कहना है कि वह माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का इस्तेमाल नहीं करना। एम्स का अपना लोकल सर्वर है। इसलिए अस्पताल के सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल का कहना है कि वे एनआइसी (राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र) का सर्वर इस्तेमाल करते हैं। यह सर्वर ठीक काम रहा था। इसलिए अस्पताल में कोई असर नहीं पड़ा।

कजाकिस्तान जा रहा विदेशी यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, 49 लाख रुपये कीमत की दवाईयां जब्त

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 49 लाख रुपये कीमत की दवाईयों के साथ एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। 19 जुलाई को सुबह लगभग 9 बजे सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में चेक-इन क्षेत्र में एक विदेशी यात्री की संदिग्ध गतिविधियों को देखा। बाद में यात्री की पहचान खबीबुल्लाव अब्दुमुतालिबजोन के रूप में की गई।

नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने शुक्रवार को दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर कजाकिस्तान के अल्माटी जा रहे एक यात्री के पास से 49 लाख रुपये कीमत की भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की दवाएं बरामद कीं।

पूछे जाने पर यात्री इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। सीआईएसएफ ने कहा कि यात्री को आगे की कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया। यात्री की पहचान खबीबुल्लाव अब्दुमुतालिबजोन खोतमजोन उगली के रूप में की गई।

सुरक्षाकर्मियों ने विदेशी यात्री की संदिग्ध गतिविधि को देखा

सीआईएसएफ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "19 जुलाई को सुबह लगभग 9 बजे सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में चेक-इन क्षेत्र में एक विदेशी यात्री की संदिग्ध गतिविधियों को देखा। बाद में यात्री की पहचान खबीबुल्लाव अब्दुमुतालिबजोन के रूप में की गई। खोतमजोन उगली (उज्बेकिस्तान नागरिक) एयर अस्थाना की उड़ान संख्या केसी-908 (एसटीडी-1135 बजे) से अल्माटी जा रहा था। एक्स-बीआईएस मशीन के माध्यम से उसके सामान की जांच की गई, जिसमें एक ट्रॉली बैग और दो कार्टन बक्से शामिल थे।"

चेक-इन प्रोसेस के बाद सीमा शुल्क कार्यालय भेज दिया

इसके बाद, यात्री को चेक-इन औपचारिकताएं पूरी करने की अनुमति दी गई और भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक उपायों के माध्यम से कड़ी निगरानी में रखा गया। चेक-इन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यात्री को सीआईएसएफ निगरानी और खुफिया कर्मचारियों ने सीमा शुल्क कार्यालय में लाया गया।

सीमा शुल्क अधिकारियों की मौजूदगी में उसके चेक-इन बैगेज की गहन जांच करने पर भारी मात्रा में कई तरह की दवाईयां मिलीं, जिनकी अनुमानित कीमत 49 लाख रुपये है। पूछताछ करने पर, यात्री इतनी बड़ी मात्रा में दवाईयां ले जाने के संबंध में सहायक दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त असर, 47 उड़ानें रद्द; 170 में हुई देरी

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण आईजीआई एयरपोर्ट से अलग-अलग शहरों को जाने वाली करीब 47 घरेलू उड़ानों को रद्द करना पड़ा। साथ ही करीब 170 उड़ानें विलंबित रहीं। इस बीच एयरपोर्ट पर यात्री परेशानी के भंवर में फंसे रहे। सबसे अधिक असर इंडिगो की उड़ानों पर देखने को मिला। रद्द उड़ानों की बात करें या विलंबित की दोनों ही स्थिति में सबसे अधिक संख्या इंडिगो की ही रही।

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में सामने आई तकनीकी गड़बड़ी का जबरदस्त असर देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट आइजीआई पर शुक्रवार को देखने को मिला। अलग-अलग शहरों को जाने वाली करीब 47 घरेलू उड़ानों को रद्द करना पड़ा, साथ ही करीब 170 उड़ानें विलंबित रहीं। इस बीच एयरपोर्ट पर यात्री परेशानी के भंवर में फंसे रहे।

सबसे अधिक असर इंडिगो की उड़ानों पर देखने को मिला। रद्द उड़ानों की बात करें या विलंबित की दोनों ही स्थिति में सबसे अधिक संख्या इंडिगो की ही रही। इंडिगो की मुंबई, पुणे, नागपुर, पटना, सूरत, देहरादून, गुवाहाटी, चेन्नई, लखनऊ, विशाखापट्टनम, वाराणसी, इंदौर, भुवनेश्वर, जम्मू, अहमदाबाद, रायपुर, कोलकाता, अमृतसर, जयपुर, बंगलुरू, उदयपुर, भोपाल, हैदराबाद, कालीकट, चंडीगढ़ सहित अनेक शहरों को जाने वाली कई उड़ानें रद्द हुई। इंडिगो की करीब 40 उड़ानें रद्द हुई। इंडिगो के अलावा एअर इंडिया एक्सप्रेस की गोआ, स्पाइसजेट की दरभंगा, मुंबई, गुवाहाटी, श्रीनगर की उड़ानें रद हुई। एअर इंडिया की मुंबई की दो उड़ानें रद्द हुई।

टर्मिनल बे में खड़े रहे विमान

घरेलू उड़ानों के लिए दिन में 12 बजे का समय काफी अहम होता है। यह समय काफी व्यस्त माना जाता है। इस समय जो विमान प्रस्थान के लिए टर्मिनल बे में खड़े थे, उनमें से अधिकांश केवल इसलिए मिनटों के बजाय घंटों खड़े रहने के लिए मजबूर रहे, क्योंकि उनके पास उड़ान भरने के लिए यात्री थे ही नहीं। यात्रियों की बोर्डिंग की प्रक्रिया काफी धीमी रही।

उड़ान के निर्धारित समय से न्यूनतम एक से डेढ़ घंटे का समय प्रस्थान के लिए विमानों को लग रहा था। बे पर जगह नहीं मिलने का असर धीरे धीरे आगमन पर भी पड़ने लगा। कई विमानों को टर्मिनल बे पर न खड़ा कर टरमैक के आसपास पार्किंग के लिए खड़ा किया गया। यहां से यात्रियों को बस द्वारा टर्मिनल लाया गया।

अंदर कतार ही कतार

सर्वर के काम नहीं करने के कारण चेकइन से लेकर बोर्डिंग व बैगेज टैगिंग की प्रक्रिया मैनुअल शुरू की गई। यात्रियों को हाथ से लिखा बोर्डिंग पास जारी किया गया। इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगने के कारण कतार अलग अलग काउंटर पर बढ़ती ही चली गई। टर्मिनल के अंदर जहां चेकइन काउंटर के पास लंबी लंबी कतार थी, वहीं टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर भी यात्रियों की काफी संख्या प्रवेश के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी।

इसका कारण यह था कि प्रवेश के डिजियात्रा के जिन गेटों से यात्री चंद मिनट में प्रवेश कर जाते थे, वह डिजियात्रा माइक्रोसाफ्ट सर्वर के ठप्प होने के कारण काम नहीं कर रही थी। ऐसे में यात्रियों को मैनुअली ही प्रवेश दिया जा रहा था। भीड़ का आलम यह था कि कई गेट पर पांच से 10 मिनट का समय यात्रियों को प्रवेश में लग रहा था। इसके बाद टर्मिनल के भीतर लगी लंबी कतार से यात्रियों का सामना हो रहा था।

जारी होती रही एडवाइजरी

सर्वर से जुड़ी तकनीकी समस्या का असर एकाएक सामने आया। एयरलाइंस वालों ने स्थिति को फौरन भांप लिया और ऐसे यात्री जिनकी उड़ानें 12 बजे के बाद थी, उन्हें संदेश भेजकर परिस्थिति से अवगत कराया। यात्रियों से कहा गया कि घर से प्रस्थान करने के पहले एक बार उड़ान की स्थिति का वेबसाइट पर पता कर लें। यात्रियों से अनुरोध किया गया कि यदि संभव हो तो चार से पांच घंटे पहले आएं ताकि चेकइन में लगने वाले समय का उड़ान पर कम से कम असर हो। यात्री जितना पहले पहुंचेंगे उनकी चेकइन की प्रक्रिया उतनी जल्दी होगी।

सुनीता केजरीवाल संभालेंगी हरियाणा विधानसभा चुनाव अभियान की कमान, 'केजरीवाल की गारंटी' करेंगी पेश

परिवहन विशेष न्यूज

आम आदमी पार्टी (आप) ने घोषणा की थी कि वह हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल शनिवार को पंचकुला से इस अभियान की शुरुआत करेंगी। सुनीता इस दौरान केजरीवाल की गारंटी भी पेश करेंगी। उनके साथ पार्टी के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को हरियाणा विधानसभा के लिए पार्टी की गारंटी की घोषणा करेगी। इसी के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी होगी। आप ने एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल शनिवार को हरियाणा के पंचकुला में एक टाउनहॉल बैठक में 'केजरीवाल की गारंटी' की घोषणा करेंगी।

इसमें कहा गया है कि उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक फिलहाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। बता दें, सुनीता केजरीवाल ने हालिया लोकसभा चुनाव में दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में पार्टी उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था।

लोकसभा चुनाव में मिली थी हार

आप ने मंगलवार को घोषणा की कि वह हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि AAP ने हरियाणा में कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन उसने अभी तक चुनावी सफलता का स्वाद नहीं चखा है। मई में हुए लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल से हार गए थे।

सावधान! कॉलेजों में बंक मारने वालों के लिए बुरी खबर, हो रही ये योजना लागू; अब अगर किया ये काम तो फिर पड़ेगा महंगा

कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो जाएं अब सावधान। क्योंकि अगर अब आपका क्लास बंक करना मुश्किल हो जाएगा। अभिभावकों तक आपके बंक की जानकारी पहुंच जाएगी। उच्चतर शिक्षा निदेशालय नए सत्र से ऑनलाइन हाजिरी योजना लागू कर रहा है। अब छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के भी प्रयास हो रहे हैं। प्रोफेसर कक्षा में जाकर छात्रों की उपस्थिति का अपडेट लेंगे।

फरीदाबाद। अब कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं अपनी कक्षा से बंक नहीं मार सकेंगे। अगर वह ऐसा करते तो इसकी जानकारी उनके अभिभावक तक पहुंच जाएगी। उच्चतर शिक्षा निदेशालय नए सत्र से ऑनलाइन हाजिरी योजना लागू करने जा रहा है।

यह योजना एक अगस्त से प्रभावी तरीके से लागू होगी। अभिभावकों को पता रहेगा कि उनका बच्चा कितने दिन कालेज गया और कौन से विषय की कक्षा में बैठकर पढ़ाई की। नए सत्र से उच्चतर शिक्षा में कई बड़े-बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। छात्रों को रोजगार एवं कौशल परख ज्ञान देने के लिए इस बार उच्चतर शिक्षा विभाग ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। इसके अलावा अन्य कई सुधार किए जा रहे हैं। अब छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से विद्यार्थी कक्षाओं में जाकर पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी कम उपस्थिति की वजह से वार्षिक परीक्षाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। पहले अभिभावकों की ओर से कालेज प्रबंधन पर दोष मढ़ दिया जाता था कि उनकी बच्चों की उपस्थिति अधिक होने के बावजूद भी उसे परीक्षा से वंचित किया जा रहा है।

प्रोफेसर कक्षा में जाकर लेंगे छात्रों की उपस्थिति का अपडेट

पहले की तरह प्रोफेसर कक्षा में जाकर विद्यार्थियों की उपस्थिति लेंगे और इसके बाद उसे ऑनलाइन भी अपडेट करेंगे। इसके लिए उच्चतर शिक्षा ऑनलाइन हाजिरी एप्लीकेशन तैयार करवा रहा है। कॉलेजों में एक अगस्त तक ऑनलाइन हाजिरी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।

इसको लागू भी कर दिया जाएगा। प्रति सप्ताह तैयार होगा रिकॉर्ड

उच्चतर शिक्षा विभाग ने शुरुआत में प्रति सप्ताह छात्र की ऑनलाइन हाजिरी का रिकॉर्ड तैयार करना होगा। सभी छात्रों की हाजिरी एक जगह कंपाइल की जाएगी और प्रत्येक महीने के अंत में यह हाजिरी आटोमेटिक छात्रों के अभिभावकों के एसएमएस के जरिये पहुंच जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन से अभिभावकों के मोबाइल नंबर को लिंक किया जाएगा।

खाकी पर गिरी गाज: चार युवकों की चौकी में लाकर की थी पिटाई, पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर से लगाई गुहार; फिर हुआ एक्शन

चार युवकों की पिटाई के मामले में तीन पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने चारों युवकों को चौकी में लाकर पिटाई की थी। इसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से मामले की शिकायत की। इसी शिकायत के आधार पर टीएसआई समेत तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पढ़िए पूरा मामला क्या है?

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। इंकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र स्थित हल्दोनी मोड़ पर कार न रोकने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने कुलेसरा चौकी में ले जाकर चारों युवकों की पिटाई की। पीड़ितों के स्वजन ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की।

इस मामले का संज्ञान लेकर एक टीएसआई, एक कांस्टेबल और चौकी के हेड कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

पुलिस कर्मियों ने किया था रुकने का इशारा

नोएडा के सलारपुर गांव का रहने वाला एक युवक रविवार को तीन दोस्तों के साथ कार से सूरजपुर जा रहा था। कुलेसरा से आगे हल्दोनी मोड़ पहुंचा तो उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी आ गया। पुलिसकर्मी ने कार चला रहे युवक से कहा कि पीछे सिपाही के इशारा करने पर कार क्यों नहीं रोकी।

आरोप है कि पुलिसकर्मी चारों दोस्तों को कुलेसरा पुलिस चौकी ले गए और पिटाई की। एक युवक ने जेब में रखे फोन से इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। जिसमें युवकों को पीटने और उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है।

पुलिस कर्मियों ने की 50 हजार की मांग

आरोप है कि युवकों को छोड़ने के एवज में पुलिसकर्मियों ने 50 हजार रुपये की मांग की। युवकों के जेब में रखे 30 हजार रुपये निकाल लिए। इसके बाद उनसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने का शिकायती पत्र जबरन लिखवाया गया। है। बाद में उन्हें कोतवाली ले जाकर छोड़ा गया।

पीड़ित युवक ने बताया कि कोतवाली से बाहर निकलते ही कार का साढ़े 14 हजार का चालान कर दिया। घर पहुंच कर उन्होंने आपबीती स्वजन को बताई।

इसके बाद युवक व उनके स्वजन सेक्टर 108 पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर को शिकायती पत्र दिया।

युवक ने ऑडियो किया था शेयर

वहीं, पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा सुनीति ने मामले की जांच कर घटना में शामिल एक टीएसआई नरेंद्र कुमार समेत चौकी के हेड कांस्टेबल आशीष तोमर व एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को निलंबित किया है। युवक ने पिटाई के समय का ऑडियो इंटरनेट पर शेयर करते हुए नोएडा और यूपी पुलिस को टैग किया है।

सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल

पलवल जिले (Palwal Crime) के बहरौला फ्लाईओवर के ऊपर एक बाइक सवार को किसी अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल का अभी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है।

पलवल। सदर थाना अंतर्गत बहरौला फ्लाईओवर के ऊपर बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के बाद आरोपित चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सदर थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने इस मामले में दर्ज किया केस

सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार (Palwal Police) के अनुसार मामले में मध्यप्रदेश के भिंड के रहने वाले रामकुमार ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसका भतीजा अंकुश गुरुग्राम में लेबर सुपरवाईजर की नौकरी करता था।

बीती 18 जुलाई को दोपहर करीब एक बजे अंकुश के भाई मुकेश को अंजान व्यक्ति ने फोन पर बताया कि अंकुश सड़क हादसे में घायल हो गया है। अंकुश के साथ एक महिला भी घायल हुई है।

बहरौला फ्लाईओवर के ऊपर हुआ हादसा

यह हादसा बहरौला फ्लाईओवर के ऊपर हुआ है। वह स्वजन को लेकर पलवल के जिला नागरिक अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचकर उन्हें पता चला कि अंकुश की बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है।

जिससे अंकुश और उसकी पत्नी सुषमा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे में सुषमा की मौत हो गई, जबकि अंकुश का उपचार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है।

रेल दुर्घटनाओं से उपजते सवालों के जवाब आखिर कौन देगा, कब तक मिलेगा

कमलेश पांडे

आंकड़े बताते हैं कि भारत के रेलवे नेटवर्क में, 64,000 किलोमीटर (40,000 मील) ट्रैक पर 14,000 ट्रेनों में प्रतिदिन 12 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। बावजूद इसके यहां रेल दुर्घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है।

लीजिए, एक और ट्रेन दुर्घटना हो गई। यह घटना उत्तरप्रदेश के गोंडा जिले में घटित हुई, इसलिए इसे गोंडा ट्रेन दुर्घटना के नाम से जाना गया। देखा जाए तो पिछले एक महीने में यह दूसरा बड़ा रेल हादसा है, जिसमें 3-4 यात्रियों की मौत हो चुकी है और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल चुके हैं। इससे एक सुलगता हुआ सवाल पैदा हो रहा है कि लाखों लोगों के लिए यात्रा का प्राथमिक साधन रेलवे अब उतना सुरक्षित नहीं रह गया है, जितनी कि उससे अपेक्षा हुआ करती है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत के रेलवे नेटवर्क में, 64,000 किलोमीटर (40,000 मील) ट्रैक पर 14,000 ट्रेनों में प्रतिदिन 12 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। बावजूद इसके यहां रेल दुर्घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। गत जून महीने में ही पश्चिम बंगाल में एक मालगाड़ी एक यात्री ट्रेन से टकरा गई, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए, क्योंकि मालगाड़ी के चालक ने सिग्नल की अनदेखी की थी।

इसी तरह से पिछले साल, पूर्वी भारत में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें 280 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जो दशकों में सबसे घातक दुर्घटनाओं में से एक थी। आलम यह है कि रेल सुरक्षा में सुधार के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद, हर साल कई एक दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनका कारण अक्सर मानवीय भूल या पुराने सिग्नलिंग उपकरण होते हैं। लेकिन लगातार हो रही इन रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण सवाल पैदा हो रहे हैं, जिनके जवाब समय रहते ही मिल जाएं तो इन दुर्घटनाओं को टाला जा सकेगा।

पहला, रेलवे की 'कवच' सुरक्षा प्रणाली अब तक केवल 1 प्रतिशत रेलवे ट्रैक को ही क्यों कवर कर पाई है? इस विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है?

दूसरा, अगर देश के पास सभी रेलवे ट्रैक पर कवच प्रणाली लगाने के साधन नहीं हैं, तो प्रधानमंत्री और रेलमंत्री कवच प्रणाली को अपग्रेड करने के बजाय बुलेट ट्रेनों और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या उनके ऊपर कोई कूटनीतिक दबाव है या फिर मित्र उद्योगपतियों और ठेकेदारों को उपकृत करने के लिए यह सबकुछ किया जाएगा।

तीसरा, लगातार रेल दुर्घटनाओं के बावजूद भारत सरकार ने रेल सुरक्षा पर खर्च करने के बजाय बुलेट ट्रेनों पर 1 लाख करोड़ रुपये क्यों खर्च किए? क्या इसके लिए रेलवे सुरक्षा के लिए आवंटित धन को डायवर्ट किया गया?

चतुर्थ, वित्त वर्ष 2024 में ट्रैक नवीनीकरण के लिए आवंटन बजट के 7.2 प्रतिशत तक ही सीमित क्यों रखा गया? क्या सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए रखरखाव और नवीनीकरण को उच्च प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए? यदि नहीं तो फिर उपाय क्या है?

पंचम, दिसंबर 2022 में सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2018 से 2021 तक 69 प्रतिशत रेल दुर्घटनाएँ रेल दुर्घटनाओं से संबंधित थीं। सीएजी निरीक्षण रिपोर्ट में गंभीर कमियों की पहचान की गई थी। लेकिन उन कमियों पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है?

छठा, रेलवे में लगभग 3 लाख रिक्तियाँ क्यों हैं? जिनमें से 1.5 लाख से अधिक सुरक्षा से संबंधित पद हैं। क्या इस सरकार के लिए यात्री सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है? या फिर इसे भी चरणबद्ध रूप से निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी चल रही है, जो समय के साथ प्रकाश में आएगा।

सातवां, लगातार दुर्घटनाओं के बावजूद मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में क्यों मिला दिया? क्या इसे उचित फैसला करार दिया जा सकता है।

आठवां, जब कतिपय जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल की विफलता, संचालन के प्रबंधन में कई स्तरों पर खामियाँ और लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के पास वॉकी-टॉकी जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण की अनुपलब्धता जैसे कुछ कारण बताए गए हैं, तो फिर उन्हें पूरा करके इन कमियों को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है?

नवम, इन तमाम गम्भीर सवालों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो आत्म-प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ते, सेल्फी और रील कल्चर के आदि हो चुके हैं, को भारतीय रेलवे में हुई भारी खामियों की सीधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

दशम, सच कहा जाए तो यह जांच का विषय है कि ट्रेन से जुड़ी कई दुर्घटनाएँ लगातार हो रही हैं, पर अपेक्षित कार्रवाई नदारत। देश में लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो वो रेल मंत्री हैं या फिर रेल महकमें के वो बड़े अधिकारी जो इन्हें रोकने के प्रति गम्भीर नहीं हैं। इसलिए पूर्व के रेल मंत्रियों की तरह ही इन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए।

अंतिम सवाल यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? वैसे तो पिछले दशक में भारत में कई रेल दुर्घटनाएँ कई कारणों से हुई हैं, जिनमें यांत्रिक विफलताओं से लेकर मानवीय लापरवाही तक शामिल हैं।

इसलिए यहाँ पर हम कुछ प्रमुख घटनाओं, उनके कारणों और अधिकारियों द्वारा कही गई बातों पर एक नज़र डालते हैं, ताकि आप यह समझ सकें।

पहला, 26 मई, 2014 को, हिसार-गोरखपुर मार्ग पर गोरखधाम एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में एक डबल-लाइन सेक्शन से गुज़र रही थी, जब इसका इंजन 11 डिब्बों के साथ पटरी से उतर गया। इस दुर्घटना का कारण ₹टंग रेल का फ्रैक्चर₹ माना गया, जो ट्रेनों को आसानी से दूसरी रेलवे लाइन पर जाने में मदद करता है, और इसे ₹उपकरण की विफलता₹ के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस घटना में कम से कम 29 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।

दूसरा, 2015 में वाराणसी-देहरादून जनता एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के एक स्टेशन पर रुकने में विफल रही, जिसके कारण 20 मार्च, 2015 को कुछ डिब्बे दुर्घटनाग्रस्त हो गए और पटरी से उतर गए। उस समय रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा था कि जब ट्रेन बछरावां स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, तब ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को पार कर लिया और रेत के ढेर में जा टकराई, जिससे ट्रेन का इंजन और दो डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में लगभग 39 यात्रियों की मौत हो गई और 150 लोग घायल हो गए।

तीसरा, 20 नवंबर, 2016 को कानपुर देहात जिले के पुखरायां इलाके में इंदौर-पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना में 152 लोगों की जान चली गई। हाल के वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई सबसे बड़ी मौतों में से यह एक है।

चतुर्थ, 21 जनवरी, 2017 को जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के कुनेरू स्टेशन पर पटरी से उतर गई। ओडिशा जाने वाली इस ट्रेन की दुर्घटना में 40 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।

पंचम, 19 अक्टूबर, 2018 को अमृतसर के नज़दीक रेलवे ट्रैक पर दशहरा समारोह देखने के लिए खड़े लोगों को दो ट्रेनों ने रौंद दिया, जिसमें लगभग 60 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। जब जालंधर-अमृतसर डीएमयू ट्रैक पर आई, तो आतिशबाजी देखने के लिए लगभग 300 लोगों की भीड़ जमा थी।

छठा, 3 फरवरी, 2019 को बिहार के वैशाली जिले में दिल्ली जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस की बोगियों के पटरी से उतरने के कारण सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना में सहदेई-बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के पास नौ ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए।

सातवां, हैदराबाद के पास चेरलापल्ली स्टेशन से नासिक के पनेवाड़ी स्टेशन जा रही एक खाली मालगाड़ी ने 8 मई, 2020 को पटरियों पर सो रहे 16 श्रमिकों को गलती से कुचल दिया। कथित तौर पर लोको पायलट ने श्रमिकों को देखा, लेकिन समय रहते ट्रेन को रोकने में विफल रहा।

आठवां, 13 जनवरी, 2022 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के डोमोहानी इलाके में बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर जाने से 10 यात्रियों की मौत हो गई और 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सीआरएस के अनुसार, पटरी से उतरने का कारण ₹उपकरण (लोकोमोटिव) की विफलता₹ थी।

नवम, 2 जून 2023 को शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी परस्पर टक्कर हुई। इन तीनों ट्रेनों की टक्कर के कारण भारत में सबसे खराब रेल दुर्घटना हुई, जिसके कारण 2 जून, 2023 को कम से कम 293 लोगों की मौत हो गई।

दशम, इस साल 7 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और कम से कम 40 लोग घायल हो गए।

बहरहाल, सरकार ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जो नाकाफी है। मृतकों के परिवारों को कम से कम 50-50 लाख का मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।

वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने 2030 तक 30% ईवी पैठ हासिल करने के लिए सरकार से किया समर्थन का आग्रह

परिवहन विशेष न्यूज

काइनेटिक ग्रीन की संस्थापक और सीईओ सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के उपयोग को मौजूदा 6% से बढ़ाकर 30% करने के लिए सरकार से कड़े कदम उठाने का आह्वान किया है। जैसे-जैसे नया बजट नजदीक आ रहा है, उन्होंने ईवी क्षेत्र के विकास को बनाए रखने के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया।

सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण यानी फेम 3 योजना की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि मौजूदा योजना 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। उन्होंने निवेश और ईवी अपनाने को ट्रैक पर रखने के लिए अगले तीन से पांच वर्षों के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने के महत्व पर जोर दिया। सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने कहा, "हमें फेम योजना को जारी रखने की तत्काल आवश्यकता है। निवेश की गति को बनाए रखना और ईवी उपयोग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।"

सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने 10-15 प्रमुख शहरों और राजमार्गों के किनारे प्रमुख क्षेत्रों में अधिक चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "पूरे भारत में इलेक्ट्रिक कारों और वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करना आवश्यक होगा।"

ईवी सेक्टर लिथियम-आयन बैटरी पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% और ईवी चार्जिंग सेवाओं पर 5% करने की भी मांग कर रहा है। सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने कहा, ₹ये बदलाव ईवी को अधिक किफायती बनाएंगे और ग्राहकों के लिए स्वामित्व अनुभव को बेहतर बनाएंगे।" सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी का मानना है कि ये उपाय 2030 तक 30% ईवी पैठ के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में एक स्थायी ईवी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेंगे।

ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट 2034 तक 18.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जाएगा पहुंच

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग के लिए वैश्विक सामग्रियों का मूल्य 2023 में 661.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2024 और 2034 के बीच, 32.7% की सीएजीआर से बढ़ते हुए, 18.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रिक वाहनों से पर्याप्त ड्राइव रेंज तभी प्राप्त की जा सकती है जब उनमें इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी लिथियम-आयन वाली हो। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता बैटरी तकनीक के विकास के साथ चार्जिंग के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की मांग को बढ़ाती है, जिससे ऊर्जा घनत्व में वृद्धि होती है और चार्जिंग का समय तेज़ होता है।

ईवी चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए स्टील, कंक्रीट और कंपोजिट जैसी अत्याधुनिक सामग्रियों की बहुत ज़रूरत होती है। टिकाऊ निर्माण सामग्री और तरीकों का उपयोग करना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का एक और तरीका है।

चार्जिंग प्रोटोकॉल और हार्डवेयर का मानकीकरण इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल और चार्जिंग नेटवर्क के बीच अंतर-संचालन सुनिश्चित करेगा। सुचारू एकीकरण और अनुकूलता के लिए एक मानक चार्जिंग कनेक्टर, केबल और संचार इंटरफ़ेस महत्वपूर्ण होगा।

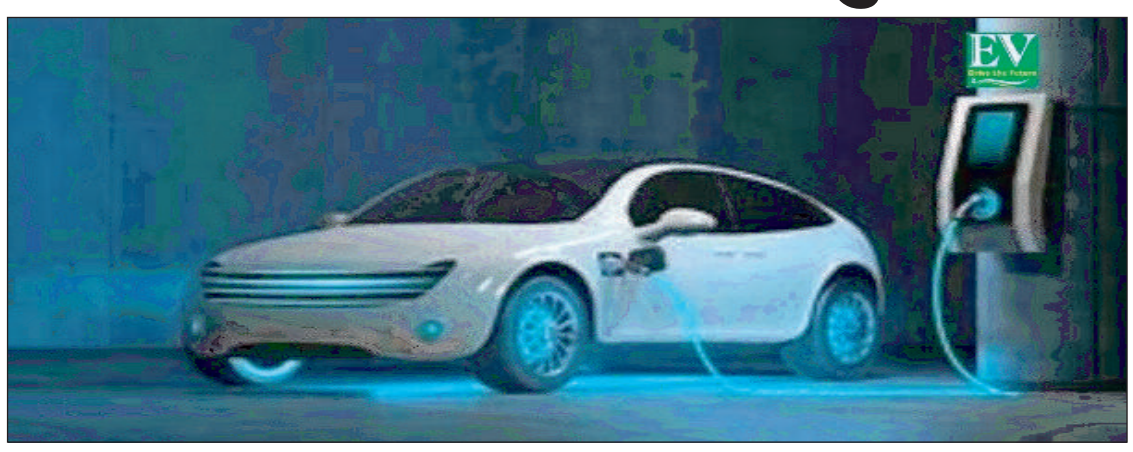

हालाँकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वायरलेस चार्जिंग तकनीक अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन भविष्य में इसका सुविधा और उपयोगकर्ता अनुभव पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वायरलेस चार्जिंग पैड, कॉइल और पावर ट्रांसफर सिस्टम में सामग्री दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाई जाएगी।

सामग्री के प्रकार के आधार पर, मिश्रित सामग्रियों का बाजार पर प्रभुत्व रहने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री से चार्जिंग स्टेशनों के लिए बाजार तैयार होने की संभावना है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के लिए सामग्रियों की मांग बढ़ेगी।

चार्जिंग स्टेशनों के संदर्भ में, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खंड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए सामग्री का बाजार तैयार करेगा।

अगले कुछ वर्षों में वाणिज्यिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की मांग काफी अधिक होगी।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना बाजार के लिए सामग्रियों की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

चार्जिंग स्टेशन की बिजली को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करने और वितरित करने की क्षमता पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर घटकों पर निर्भर करती है। तेज़ चार्जिंग के अलावा, यह सामग्री द्विदिशीय बिजली हस्तांतरण और स्मार्ट ग्रिड एकीकरण में भी सक्षम है।

सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बड़ी संख्या में ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। ईवी चार्जिंग से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन के लिए सौर पैनल, पवन टर्बाइन और ऊर्जा भंडारण उपकरण जैसी सामग्री आवश्यक है।

डेटा कनेक्टिविटी और संचार उपकरण नेटवर्क प्रबंधन, दूरस्थ निगरानी और भुगतान प्रसंस्करण के लिए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के आवश्यक घटक हैं। ईवी चार्जिंग नेटवर्क को भरोसेमंद और सुरक्षित बनाने के लिए, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा और दूरसंचार के लिए सामग्री आवश्यक है।

सरकारी नीतियाँ, प्रोत्साहन और सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। स्थिरता, नवाचार और ऊर्जा दक्षता का समर्थन करने वाली सरकारी पहलों का ईवी के उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों और उन्हें चार्ज करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ सकता है।

ई-रिक्शा चालक समिति ने गरीब कन्या के विवाह के लिए दिए 51000 रुपये

परिवहन विशेष न्यूज

धार्मिक नगरी वृंदावन में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ ई-रिक्शा चालकों की हरसंभव मदद करने में जुटी वृंदावन ई-रिक्शा समिति ने अपना संकल्प पूरा कर मिसाल कायम की है।

समिति के पदाधिकारियों ने समिति से जुड़ी एक महिला की बेटी की शादी में 51 हजार रुपये का घरेलू सामान उपहार स्वरूप दिया है। जिसके लिए समिति से जुड़े सैकड़ों ई-रिक्शा चालकों ने समिति के सदस्यों का आभार जताया है।

यहां आपको बता दें कि धार्मिक नगरी वृंदावन में ई-रिक्शा के समुचित संचालन की जिम्मेदारी प्रशासन की देखरेख में वृंदावन ई-रिक्शा समिति को सौंपी गई है। जिसके लिए समिति के पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं।

एक बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने कहा था कि वे समिति से जुड़े सदस्यों की गरीब बेटियों की शादी में 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी करेंगे।

समिति के सदस्यों ने अपने द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करते हुए गत शुक्रवार, 12 जुलाई को काशीराम कालोनी स्थित ब्लॉक संख्या 10 रहने वाली एक निर्धन कन्या के विवाह के लिए कन्यादान स्वरूप 51000 रूपये का घरेलू सामान भेट किया है। जिसके लिए परिवार के सदस्य व समिति से जुड़े सैकडो ई-रिक्शा चालकों ने समिति के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया हैं।

कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपए का घरेलू सामान भेंट करते समय ई-रिक्शा चालक समिति के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह, समाजसेवी ताराचंद गोस्वामी, ई-रिक्शा चालक समिति के सदस्य अजीत सिंह सहित समिति के सदस्यगण भी मौजूद थे।

कोलकाता में जल्द ही तैयार हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट

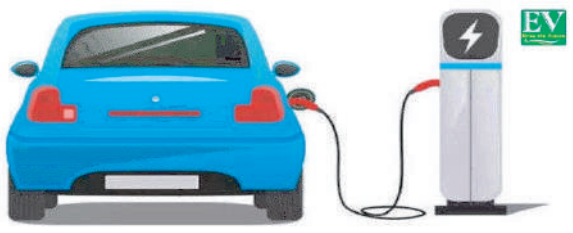

परिवहन विशेष न्यूज

भारत के अन्य शहरों की तरह कोलकाता में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए कोलकाता के लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। कोलकाता में ईवी वाहनों का खूब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनके चार्जिंग प्वाइंट को लेकर लोग अक्सर चिंतित रहते हैं, लेकिन अब कोलकाता के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोलकाता नगर निगम की ओर से महानगर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट तैयार किए जा रहे हैं। कोलकाता नगर निगम का लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी विभाग इन चार्जिंग प्वाइंट को तैयार करेगा। इन्हें तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। यह जानकारी विभाग के मेयर परिषद के सदस्य संदीप रंजन बख्शी ने दी।

शहर में चार जगहों पर चार्जिंग प्वाइंट तैयार किए जा रहे हैं। विभाग के महानिदेशक (डीजी) संजय भौमिक ने बताया कि निगम के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास स्थित निजाम रेस्टोरेंट, गरियाहाट मार्केट, ईएम बाईपास स्थित स्वभूमि और निगम के सेंट्रल गैराज में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट तैयार किए जाएंगे। सेंट्रल गैराज स्थित चार्जिंग प्वाइंट का इस्तेमाल सिर्फ निगम के वाहनों के लिए होगा। इसके अन्य तीन इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट पर एक साथ दो वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। चार्जिंग प्वाइंट हाई स्पीड होगा, जिसमें डुअल गन की सुविधा होगी।

डीजी श्री भौमिक ने कहा कि लोग 15 रुपये प्रति यूनिट की दर से अपने वाहन चार्ज कर सकेंगे। वाहन मात्र 45 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन को 200 रुपये में चार्ज करता है तो वह 300 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। डीजी ने कहा कि इन चार्जिंग पॉइंट का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। दुर्गा पूजा से पहले काम पूरा करने की योजना है।

स्विच मोबिलिटी ने 1.25 टन इलेक्ट्रिक एलसीवी IeV3 का किया अनावरण

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हिंदुजा समूह की इलेक्ट्रिक बसों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों की वैश्विक निर्माता कंपनी स्विच मोबिलिटी ने 1.25 टन पेलोड श्रेणी में अपने IeV3 की चाबियाँ सौंपकर टिकाऊ शहरी लॉजिस्टिक्स में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। IeV4 की सफलता के बाद, IeV3, IeV श्रृंखला का नवीनतम उत्पाद है और स्विच मोबिलिटी के सीईओ महेश बाबू ने आधिकारिक तौर पर ग्राहकों को चाबियाँ सौंपीं।

महेश बाबू ने कहा कि IeV3 को ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें उन्नत बैटरी तकनीक, प्रभावशाली रेंज और बुद्धिमान डिज़ाइन है। इसकी प्रतिस्पर्धी कीमत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक रणनीतिक विकल्प बनाती है, जो एक टिकाऊ भविष्य की ओर बदलाव को गति देती है।

25.6 kWh की बैटरी और 1,250 किलोग्राम की पेलोड क्षमता से लैस, इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल वाहन एक विशाल कार्गो वॉल्यूम और 140 किमी की रेंज प्रदान करता है। 40 kW की मोटर और 190 Nm के टॉर्क के साथ, यह बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, iON सिस्टम, एक मालिकाना कनेक्टेड टेक्नोलॉजी टेलीमैटिक्स समाधान, वास्तविक समय के डेटा और एनालिटिक्स प्रदान करके वाहन की दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाता है, जिससे व्यवसायों को स्मार्ट और अधिक लागत प्रभावी प्रबंधन के लिए अपने बेड़े के संचालन की निगरानी और अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है।

ई-रिक्शा चालकों को बताए गए यातायात नियम

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा के खंदारी बाईपास रोड स्थित मनोरम बजाज शोरूम में ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियम बताए गए। उन्हें आर्थिक आजादी के लिए ईवी ऑटो खरीदने की सलाह दी गई। शोरूम में गुरुवार 18 जुलाई को आयोजित कार्यशाला में बजाज ऑटो के नॉर्थ एरिया हेड कनिष्क श्रीवास्तव ने ई-रिक्शा चालकों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आसान किस्तों पर ईवी ऑटो खरीदने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कम समय में अधिक सवारियां ढोकर अच्छा मुनाफा कमाने के लिए बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो आज सबसे अच्छा विकल्प बन गया हैं। उन्होंने लोन, डाउन पेमेंट आदि से जुड़ी जानकारी भी साझा की।

मनोरम बजाज के एमडी राम मोहन कपूर ने यातायात नियमों के बारे में बताया। कार्यशाला का संचालन सीईओ गौरव कपूर ने किया।

भोपाल, इंदौर समेत 10 जिलों में पराली और पत्तों से बायो-सीएनजी बनाएगा रिलायंस ग्रुप

परिवहन विशेष न्यूज

रिलायंस समूह प्रदेश के दस जिलों में बायोगैस प्लांट (बायो-सीएनजी) लगाने की तैयारी कर रहा है। इसमें 1500 करोड़ का निवेश होगा और 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा करीब 20 लाख किसानों को होगा। प्लांट के लिए किए गए शुरुआती सर्वे में कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता बताई गई है। पराली, पेड़ों की पत्तियों, शहरों के सूखे कचरे से सीएनजी गैस तैयार की जाएगी। कंपनी खुद किसानों के खेतों से पराली और पेड़ों की पत्तियों को पैक करवाकर प्लांट तक पहुंचाएगी। किसानों से खरीदी और बिक्री का अनुबंध भी किया जाएगा।

फिलहाल रिलायंस ग्रुप ने भोपाल और इंदौर समेत पांच जिलों में प्लांट लगाने के लिए शहर के पास 15 से 20 एकड़ जमीन खरीदी है। प्लांट के पास ही कच्चे माल के लिए गोदाम भी बनाए जाएंगे, ताकि कम लागत में ज्यादा बायोगैस बनाई जा सके। पराली के अलावा किसानों से गेहूं, चना, राई का भूसा, धान के सूखे पौधे और सूखी घास भी खरीदी जाएगी। इसके साथ ही चावल मिलों से धान की भूसी खरीदने का भी करार किया जाएगा।

बायो गैस का उपयोग सीएनजी वाहनों और रसोई गैस में ईंधन के रूप में किया जाएगा। कंपनी गैस तैयार कर इसे पेट्रोल पंपों को उपलब्ध कराएगी। पेट्रोल डीजल की तुलना में काफी कम वाहन प्रदूषण होता है। इससे शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा।

बंजर भूमि और बीहड़ों में नेपियर घास लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस घास की खेती के लिए रिलायंस समूह किसानों से अनुबंध करेगा और घास की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराने में भी किसानों की मदद करेगा। इस घास की खासियत यह है कि यह बहुत लंबी और घनी होती है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। नेपियर घास का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाएगा और सूखने के बाद पत्तियों और डंठलों का उपयोग बायोमास प्लांट से गैस बनाने में किया जाएगा।

इससे बनने वाली राख से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। किसान भी इस राख को अपने खेतों में डालकर अपनी पैदावार बढ़ा सकेंगे। कंपनी इसे किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। साथ ही इसे सुरक्षित रखने के लिए प्लांट के पास एक गोदाम भी बनाया जाएगा, ताकि खराब होने वाली सामग्री को बारिश में बहने और गर्मियों में हवा में उड़ने से रोका जा सके।

मध्य प्रदेश के जिलों के गांवों में प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीनें भोपाल में छावनी पठार, इंदौर में डकाचिया, जबलपुर में नागना, सतना में बचवाई, बालाघाट में धंसुआ, एमपीआईडीसी भूमि आवंटन प्रक्रिया मुबारकपुर, उज्जैन में कचनारिया क्षेत्र हैं। यहा पर प्लांट लगाने से पहले कच्चे माल की उपलब्धता का पता लगाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी चंद्रमौली शुक्ला ने कहा कि रिलायंस ग्रुप सीबीजी (बायो-सीएनजी) प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। कुछ जगहों पर ग्रुप ने अपनी जमीन पर प्लांट लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। कुछ जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों में सीबीजी प्लांट लगाने के लिए सरकारी जमीन की मांग की गई है।

संसद नई, परंतु शासन पुराना

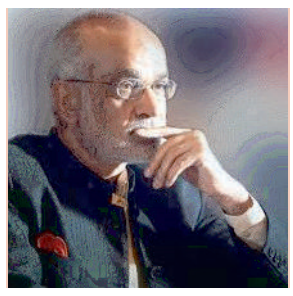

भानु धमीजा

राहुल गांधी की टिप्पणी को हटाने में बिड़ला का पक्षपात पूरे प्रदर्शन पर था। उन्होंने सत्तारूढ़ दल की नीतियों और विचारधारा पर एक विपक्षी नेता के हमले को थोक में हटाने का आदेश दिया। लोकसभा का नियम 380, जो स्पीकर को ऐसा करने का अधिकार देता है, सत्तारूढ़ दल के हाथ एक सत्तावादी उपकरण है'

भारत के हालिया संसदीय चुनावों के विषय में कहा गया था कि इन्होंने देश का लोकतंत्र बचा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के शासन की सत्तावादी शैली की आलोचना करने वाले कई भारतीयों का मानना था कि चूंकि भाजपा अपना पूर्ण बहुमत खो चुकी है, इसलिए वह अन्य दलों के प्रति अधिक संयमित और उदार होंगे। लेकिन नए राजनीतिक समीकरण के कुछ ही दिनों के भीतर, संसदीय कार्यवाही और सरकारी कार्रवाइयों से पता चलता है कि भारत एक 'चुनावी निरंकुशता' बना हुआ है, जहां चुनाव होते हैं लेकिन शासन निरंकुश है। यह लेबल 2021 में स्वीडन के वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा भारत को दिया गया था।

संसद में मोदी सरकार के नए गठबंधन सहयोगी, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), जिनके बीच 28 सीटें हैं, भाजपा के साथ पूरी तरह से कदम मिलाकर चलने लगे हैं। जब एक कट्टर भाजपा नेता ओम बिड़ला को फिर से लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो उनकी ओर से एक आवाज भी नहीं उठी। वे उस समय भी कदमताल करते दिखे जब बिड़ला ने सदन के रिकॉर्ड से विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे पर हमला करने वाली टिप्पणी को हटाने का फैसला किया। विपक्षी नेताओं के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई राज्यसभा में भी की गई, जो हाल के चुनावों से अप्रभावित थी और भाजपा के वफादार, उपाध्यक्ष धनखड़ की अध्यक्षता में पहले की तरह काम कर रही है।

नई मोदी सरकार पिछली सरकार से भिन्न नहीं है। वफादारों को प्रमुख विभागों को सौंपा गया है, और शीर्ष चार मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमित शाह को फिर से गृह, निर्मला सीतारमण को वित्त, एस. जयशंकर को विदेश, राजनाथ सिंह को रक्षा सौंपा गया है। आठ कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया गया, लेकिन मोदी लगभग सभी के शीर्ष पर बने हुए हैं।

अगर मोदी के आलोचक चुनाव के बाद एक विनम्र व्यक्ति की उम्मीद करते हैं, तो ऐसे कोई संकेत नहीं हैं। ''मोदी अभी भी मजबूत हैं'', उन्होंने पिछले हफ्ते संसद में दो घंटे के भाषण में घोषणा की। उन्होंने कहा, ''मैं भारत के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि न मोदी डरने वाला है और न ही उसकी सरकार।'' ऐसा दबंग बयान उल्लेखनीय है क्योंकि हाल के चुनाव परिणामों को दुनिया भर में मोदी की प्रतिष्ठा के लिए एक गंभीर झटके के रूप में देखा गया था। उनकी पार्टी ने न केवल अपनी 303 लोकसभा सीटों में से 92 सीटें खो दीं, बल्कि फैसला व्यक्तिगत हार भी था क्योंकि भाजपा का पूरा अभियान उनके इर्द-गिर्द ही बुना गया था। चुनावों ने मोदी के मुख्य विरोधी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नए-नवेले गठबंधन के रूप में मरणासन्न विपक्ष को भी पुनर्जीवित किया।

परिणामों से मोदी के आलोचकों में उम्मीद जगी थी क्योंकि ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र के बहुलवाद का एक प्रभावशाली प्रदर्शन थे जिन्होंने उन्हें गठबंधन बनाने के लिए विवश किया। उनकी भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अब 14 अलग-अलग दलों के समर्थन पर निर्भर है, जिनमें से अधिकांश के पास केवल एक या दो संसदीय सीटें हैं। टीडीपी और जेडीयू दो क्षेत्रीय दल गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी हैं।

लेकिन भारत में अच्छे चुनाव परिणाम जरूरी नहीं कि सुशासन में तब्दील हों, क्योंकि हमारी सरकार की प्रणाली स्वाभाविक रूप से सत्तावादी है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत, भारत की संसदीय प्रणाली कार्यकारी और विधायी शक्तियों को अलग-अलग नहीं करती है, या राज्य और स्थानीय सरकारों को स्वतंत्र नियंत्रण नहीं देती है, या संसद सदस्यों को अपनी पार्टियों के खिलाफ मतदान करने की अनुमति नहीं देती है। इसके बजाय, यह प्रधानमंत्री को सर्वशक्तिमान बनाती है, जो कानूनों, जांच एजेंसियों, पार्टी तंत्र, करदाताओं के पैसे आदि के साथ मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के रूप में सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री पहले भी देखे हैं।

एक सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री को गठबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब गठबंधन के सहयोगी एनडीए की तरह छोटे और क्षेत्रीय हों। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिए केवल धन और समर्थन हासिल करने में रुचि रखते हैं। वे मोदी के राष्ट्रीय एजेंडे या कार्यशैली के साथ कुश्ती करने की संभावना नहीं रखते हैं। न ही वे गठबंधन को धमकाने की स्थिति में हैं, क्योंकि भाजपा के विशाल संसाधनों, जांच एजेंसियों पर नियंत्रण और सांसदों को पार्टियां बदलवाने के अनुभव के बूते उन्हें बदला जा सकता है।

इसलिए, भारत में निरंकुशता जारी है, जैसा कि पिछले सप्ताह संसद में स्पष्ट था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के विपरीत, जहां सदस्य जमकर लड़े गए मतपत्रों से अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, भारत के लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नियंत्रित की जाती है। एक बार चुने जाने के बाद, एक अध्यक्ष को पद खोने का कोई खतरा नहीं, जब तक कि वह पीएम के अनुसार काम करना जारी रखता है। इसके विपरीत, अमेरिकी सदन में हाल के एक एपिसोड में, केविन मैकार्थी को स्पीकर के रूप में चुने जाने के लिए 15 मतपत्र लगे, और उन्हें अपनी ही पार्टी के सदस्यों द्वारा नौ महीने से भी कम समय में कार्यालय से बाहर कर दिया गया।

भारत का लचीला अध्यक्ष, जिसे पार्टी नेता और प्रधानमंत्री नियंत्रित करते हैं, पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता है। वह अपने आका को प्रसन्न करने के लिए सांसदों को निलंबित करता है, उनकी टिप्पणियों को हटा देता है, बहस को बंद कर देता है, और विधानसभा को भंग कर देता है। राहुल गांधी की टिप्पणी को हटाने में बिड़ला का पक्षपात पूरे प्रदर्शन पर था। उन्होंने सत्तारूढ़ दल की नीतियों और विचारधारा पर एक विपक्षी नेता के हमले को थोक में हटाने का आदेश दिया। लोकसभा का नियम 380, जो स्पीकर को ऐसा करने का अधिकार देता है, सत्तारूढ़ दल के हाथ एक सत्तावादी उपकरण के अलावा और कुछ नहीं है। यह अध्यक्ष, जो कि स्वयं सत्तारूढ़ दल का सदस्य है, को बगैर उचित प्रक्रिया या उपचार के सम्पूर्ण अधिकार देता है।

अमेरिकी सदन में, इसके विपरीत, किसी सदस्य की अनुचित या असंसदीय टिप्पणियों को हटाने के लिए एक 'व्यवस्था' निर्धारित है। किसी अन्य सदस्य को औपचारिक मांग करनी चाहिए, आरोप लगाने वाला सदस्य टिप्पणी वापस ले सकता है, अध्यक्ष सदन के नियुक्त पार्लमेंटरीअन से परामर्श कर सकता है, और यदि टिप्पणियों को हटा दिया जाता है तो अपील की एक प्रक्रिया होती है। नतीजतन, 50 साल की अवधि में 170 बार टिप्पणी हटाने की मांग उठी, परंतु अमेरिकी स्पीकर ने केवल 25 वक्तव्यों को हटाने का आदेश दिया। लगभग हर मामले में, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक सदस्य दूसरे सदस्य पर व्यक्तिगत हमले कर रहा था।

यदि भारत वास्तव में एक ऐसी संसद की कामना करता है जो काम करे और ऐसा शासन हो जो कम निरंकुश हो, तो उसे प्रधानमंत्री कार्यालय में शक्तियों का केंद्रीकरण कम करना होगा। केवल प्रधानमंत्री या अध्यक्ष को अधिक संयम और कम पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए उपदेश देने से बात नहीं बनने वाली।

संपादक की कलम से

कैडर कितने कोस का

कैडर की पड़ताल में कुछ विभाग अपनी रूपरेखा में स्तरोन्नत होना चाहते हैं, लेकिन विसंगतियों का ढर्रा चैन का बिगुल फूंकने नहीं देता। अभी पटवारी-कानूनगो की जिम्मेदारियों का आकलन राज्यस्तरीय करने का बीड़ा ही उठाया है कि सारा विभाग अपने दारोमदार में फंस गया। राजस्व विभाग जितना पारंपरिक है, उतना ही स्थानीय भी है, इसलिए फर्ज की हिदायतें जिला कैडर की सीमा में पल्लवित होती रहीं। राज्य कैडर के विरोध में संयुक्त पटवारी-कानूनगो एसोसिएशन ने ऑनलाइन सेवाओं का बहिष्कार कर दिया है और यह सीधे-सीधे आम आदमी की फरियादों के खिलाफ मुहिम बन रहा है। किसान, बागबान, युवा तथा जीवन के अनेक कार्यों में, राहत पाने की उम्मीद में राजस्व विभाग की अर्जियां शर्मिंदा हैं क्योंकि विभाग का संघर्ष अपने कैडर से है। आखिर सरकारी भूमिका है, फिसल सकती है या जनता के गुरूर को तोड़ सकती है। विभागीय गुणवत्ता के अक्स में सरकारें शिद्दत से लगी हैं, लेकिन मेहनताना है कि वर्षों से पूरा नहीं हो रहा। कैडर तो एचआरटीसी में होता है, जहां जनता की मंजिलों पर नौकरी का पैमाना और यात्रा का नक्शा होता है। किसी बस का चालक या परिचालक मीलों की लंबाई में अगर कैडर हो जाए, तो अपने राज्य के अलावा दिल्ली पहुंचने से पहले वे पंजाब और हरियाणा के अलावा दिल्ली के कैडर बन सकते हैं।

अगर कुल्लू से चला शहतीर कांगड़ा पहुंच जाए, तो उसके ऊपर मोहर लगाने वाले का कैडर कहां तक पहुंच जाएगा। राज्य में कैडर बनाम सुविधा तो है नहीं इसलिए कुछ कार्यालय व पद ऐसे भी बना दिए गए जहां प्रशासनिक अधिकारी भी आराम से होम डिस्ट्रिक्ट में पसर जाते हैं। यहां सवाल यह भी कि पटवारी-कानूनगो का पद है कितने कोस का। यह सही है कि अब तक इनकी नियुक्तियों का आधार जिलों तक हुआ, मगर अब तो सैन्य सेवाओं की भर्ती भी राज्य के कोटा में होती है तो क्या सैनिक प्रदेश की छावनियों तक सिमटे रहें। बेशक राजस्व विभाग में स्थानीय बोली का तर्क मान लिया जाए कि संवाद में आसानी होगी, लेकिन जरा परचे की भाषा का अनुवाद करके बता देना कि इस भाषा से आम आदमी का क्या लेना-देना होता है। कई विभागीय प्रणालियों की दुरुस्ती के लिए यह जरूरी है कि राज्य स्तरीय कार्य संस्कृति का प्रसार हो। मसला कैडर का बन रहा है, जबकि होना यह स्थानांतरण नीति के साथ चाहिए। आज राज्य और जिला कैडर का महत्त्व गौण है और गौण हैं ट्रांसफर ऑडर। गौण तो दायित्व भी है क्योंकि कुछ विभाग केवल निचले स्तर पर, आउट सोर्स पर या नेताओं की फरमाइश पर चल रहे हैं। जल शक्ति विभाग और जनता के बीच सारे परमार्थ फिटर के हिस्से आ गए, क्योंकि उससे बड़े व आला अधिकारियों को यह भी मालूम नहीं 'पानी आए कहां से और जाए कहां रे'।

उन्हें फील्ड का अता पता नहीं। कुछ यही हाल बिजली महकमे का भी है जहां बुझते बल्ब की निशानी में, कोई लाइन मैन दीपक बन कर जुगनूं की तरह जल रहा है, लेकिन अधिकांश कर्मचारी अब अपने कार्यालय में हस्ताक्षर नहीं करते, बल्कि अपने ही गांव के परिधि में रहते हैं। महकमे और भी हैं और हर दिशा में हैं, लेकिन एक स्थायी स्थानांतरण कैडर बन चुका है, जिसे सिर्फ यह मालूम है कि किस तरह अपने गृह क्षेत्र की परिधि में हमेशा पांव पसारे रखने हैं। पटवारी-कानूनगों कोई भिन्न प्राणी नहीं हो सकते, उन्हें भी अपने क्षेत्र की जनता के साथ काम करके आत्मसंतुष्टि मिलती होगी, लेकिन प्रशासनिक सुधारों और सुशासन की दृष्टि से अब समस्त कर्मचारी वर्ग के लिए घर से पच्चीस, पचास व सौ किलोमीटर की दूरी का स्थानांतरण फार्मूला बनना चाहिए और इसी के अनुरूप विशेष पैकेज भत्ते और आवासीय व्यवस्था होनी चाहिए।

राय

स्थानीय आरक्षण की सियासत

न जाने क्यों कर्नाटक सरकार को 'स्थानीय आरक्षण' वाला विधेयक फिलहाल स्थगित करना पड़ा! कर्नाटक सरकार की नीयत और उसके मंसूबे विधेयक में साफ झलकते हैं, जिसे राज्य कैबिनेट ने पारित किया था। पारित विधेयक भारतीय संविधान की भावना और उसका अक्षरशः उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 19 (1) के तहत देश का प्रत्येक नागरिक, देश के किसी भी हिस्से में, कारोबार या नौकरी कर, अपनी आजीविका कमा सकता है। किसी भी क्षेत्र की भाषा, जाति, धर्म और राज्यवाद उस पर प्रतिबंध नहीं थोप सकते। इसी तरह स्थानीय भाषा और नागरिकता के आधार पर आरक्षण तय करना भी 'असंवैधानिक' है। कर्नाटक कैबिनेट ने जो बिल पारित किया था, उसके मुताबिक निजी क्षेत्र के उद्योगों, फैक्टरियों और अन्य कंपनियों में प्रबंधकीय श्रेणी के पदों पर 50 फीसदी आरक्षण कन्नड़भाषी लोगों के लिए होगा। गैर-प्रबंधकीय पदों के लिए कन्नड़वालों के लिए 75 फीसदी आरक्षण होगा। सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' तभी मिलेगा, जब इस आरक्षण की पुष्टि हो जाएगी। कन्नड़ भाषा का ज्ञान, कन्नड़ परिवार में जन्म आदि शर्तें आरक्षण के लिए अनिवार्य हैं। यदि किसी पद के लिए पात्र, योग्य, कुशल कर्मचारी न मिले, तो यह दायित्व भी कंपनी का होगा कि वह अपात्र व्यक्ति को भी अपने साथ रखे और तीन साल के अंतराल में प्रशिक्षित करे। रोजगार और नियुक्ति कन्नड़वाले को ही मुहैया की जाएगी। दरअसल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी का गढ़ है। वहां 67,000 से ज्यादा देशी-विदेशी आईटी कंपनियां काम कर रही हैं। उन कंपनियों में नौकरी सिर्फ योग्यता के आधार पर मिलती है, क्योंकि काम ही तकनीकी और प्रौद्योगिकी का है। बेंगलुरु में देश के अन्य क्षेत्रों और विदेशों से भी लोग आईटी की नौकरी करने आते हैं और बेंगलुरु के युवा विदेशों में भी नौकरी करने जाते हैं। क्या ऐसे क्षेत्र में आरक्षण तर्कसंगत है? बेंगलुरु के अलावा मुंबई हमारे देश का नंबर एक महानगर है, जहां देश के कोने-कोने से लोग नौकरी करने आते हैं। वहां मराठा के नाम पर ऐसा आरक्षण नहीं है कि अन्य भारतीयों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएं। कर्नाटक कोई पहला राज्य नहीं है, जहां कैबिनेट ने 'स्थानीय आरक्षण' का बिल पारित किया है। इससे पहले आंध्रप्रदेश (2019) और हरियाणा सरकार (2020) अपने भाषायी और स्थायी नागरिकों के लिए 70-75 फीसदी आरक्षण का कानून बना चुकी हैं। बीते साल नवंबर में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थानीय आरक्षण की व्यवस्था और कानून को खारिज कर दिया था। आंध्र उच्च न्यायालय ने भी स्थानीय आरक्षण को 'असंवैधानिक' करार दिया है, जबकि यह बिल आंध्र विधानसभा में मई, 2019 में पारित किया जा चुका था। दरअसल यह भी आरक्षण के बुनियादी मुद्दे सरीखा है। यह भरपूर सियासत भी है। सरकारें स्थानीय आरक्षण को इसलिए लागू करना चाहती हैं, क्योंकि वे अपने मतदाता को रोजगार मुहैया कराना चाहती हैं। यह लाभ उन्हें बाहर के लोगों से नहीं मिल सकता, लेकिन सवाल यह भी है कि कन्नड़वाले बाहर के क्षेत्रों में भी काम करने जाते हैं। हरियाणा के असंख्य लोग दिल्ली और अन्य शहरों में व्यापार करते हैं, नौकरियां करते हैं। क्या उन सभी को प्रतिबंधित किया जा सकता है? यह अवधारणा भी संविधान के खिलाफ है। दरअसल बेरोजगारी पूरे देश की भीषण समस्या है। सरकारों और राजनीतिक दलों के लिए गंभीर चुनौती है। अब भी बेरोजगारी की राष्ट्रीय दर 9 फीसदी के करीब है, जो भयानक है। ऐसे आरक्षण से देश में इंस्पेक्टर राज की वापसी भी हो सकती है, क्योंकि नौकरशाहों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि औसत कंपनी में कितने स्थानीय कर्मचारी हैं अथवा नहीं हैं।

आहत बापू के बोल'

आज हमारे बीच गांधी होते तो रंज और मलाल से अपना सिर पकड़ लेते। आज न तो उनके अनशन की पूछ होती और न ही सत्याग्रह चल पाता। घोटालों की बाढ़ में उनके कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे क्या करें या क्या न करें? ऐसी सरकार जिसमें बेमियादी अनशन करने वालों को खुद ही अनशन तोडना पड़े तो गांधी बेचारे आखिर करते भी क्या? गूंगी और बहरी बनी सरकार गांधी की गलफांस बन जाती। इस नक्कारखाने में लंगोटी वाले की सुनता भी कौन? मैं खुद आहत हूं, पसोपेश में हूं। गांधी चौक पार्क में जाकर गांधी की प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया। अपलक उन्हें देखता रहा, आवाज आई – ''क्यों बेटा क्या बात है? मुझे जिस काल में कोई देखना नहीं चाहता, ऐसे में तुम अपना आहत हृदय लेकर क्यों वक्त बरबाद कर रहे हो?'' ''बाबा, देश का क्या होगा?'' मैंने प्रश्न किया तो मंद मुस्कान के साथ आवाज आई -''किसका देश और कौनसा देश?'' ''बापू आपका भारतवर्ष।'' मेरे यह कहने पर प्रतिमा ने उत्तर दिया - ''यह तुम्हारा वहम है बेटा। भारत नहीं, यह अंग्रेजों का इंडिया बन गया है फिर से। भारत होता तो उसके सिद्धांत और संस्कृति का चलन होता। बेटा भारत बहुत पीछे छूट गया है। देशभक्ति का जज्बा आज है किसमें? सब इसे बेतहाशा गति से लूट रहे हैं। अब यह सोने की चिडिया नहीं रहा है। दूध-दही की नदियां नहीं बहती अब। चाय को राष्ट्रीय पेय बनाने की बहस चल रही है।

बूचडख़ानों में रोज हजारों गायों की हत्याएं हो रही हैं। इसलिए दुखी होने से क्या फायदा। जाओ तुम भी इसी भीड़ में शामिल हो जाओ।'' मैं बोला -''नही बापू, इस देश को रास्ता दिखाओ, वरना यह तो आत्मघात की ओर बढ़ रहा है।'' ''बेटा, मैंने अन्ना नाम का एक बूढ़ा भेजा था, लोग उसे बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं और उसकी किसने सुनी। जंतर-मंतर से वह भी चला गया। राजघाट आया, तब मैंने उससे कहा था -''अन्ना, मत सिरफोड़ी करो। जाओ गांवों में गरीबों की सेवा करो। लेकिन टीम के बहाने आए लोग ही सत्ता सुख के सपने देखने लगे। उसकी दशा आज मेरी जैसी ही है। आहत होकर पड़ा है। निर्णय लेने की क्षमता इस मारामारी और आपाधापी के युग में खत्म हो गई है।'' ''तो बापू, मैं क्या करूं? मैं बहुत दुखी हूं। यहां का एक साधारण आम गरीब हूं। पेट की आग शांत करने का मार्ग सुझाओ।'' मैंने पूछा तो बापू बोले-''गरीब हो, यह मेरा और तुम्हारा दुर्भाग्य है। गरीबी हटाओ के कार्यक्रमों में तुमने देख ही लिया। नेता सब हड़प जाते हैं। गरीब रोते हैं। जिस देश का नेता भ्रष्ट हो, उसे भला कौन संभाल सकता है। जाओ अपने घर। मैं क्या बताऊं पेट की आग बुझाने का मार्ग!'' मैंने देखा बापू की प्रतिमा से दो बूंद अश्रु ढुलक पड़े। बोले - ''बेटा मुझे जगह-जगह पूरे देश में खड़ा कर दिया गया है। मेरे आदर्श आज धूल चाट रहे हैं। जाओ, अपने घर जाओ। हां, आत्महत्या मत करना, इतनी सी मेरी तुमसे प्रार्थना है।'' गांधी इसके बाद मौन हो गए। मैं बहुत देर तक उन्हें देखता रहा, लेकिन वे बोले कुछ नहीं।

पूरन सरमा

विचार

अब होगा नगद ईनाम वितरण समारोह

भूपिंदर सिंह

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में ड्रिल व खेलों के लिए एक पीरियड, जो वर्षों पहले पढ़ाई के नाम पर खत्म कर दिया था, अब फिर से शुरू करने का क्रांतिकारी कदम उठाकर सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों की फिटनेस को ध्यान में रखने को तो जरूर कहा है, मगर वह धरातल पर कहीं भी दिख नहीं रहा है। सरकार ने स्कूली स्तर पर खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं के लिए समय सीमित कर दिया है'

देर बाद ही सही, नगद ईनाम बांट समारोह आयोजित करने के लिए विभिन्न जिला खेल अधिकारियों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के नाम खिलाडियों से लेकर हिमाचल प्रदेश खेल परिषद को भेज दिए हैं और अब पंद्रह अगस्त को हिमाचल प्रदेश सरकार ईनाम बांट समारोह करने जा रही है। पिछली भाजपा की जयराम सरकार ने राज्य के खिलाडियों द्वारा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीते गए पदकों की ईनामी राशि को काफी सम्मानजनक स्तर तक तो जरूर बढ़ाया है, मगर पदक विजेताओं के लिए ईनाम बांट समारोह का आयोजन नहीं हो पाया था। कांग्रेस सरकार को भी चुने हुए दूसरा वर्ष भी आधा खत्म हो रहा है, मगर यह सरकार भी अब राज्य के वरिष्ठ व कनिष्ठ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए ईनाम बांट समारोह आयोजित करने जा रही है। हां, यह अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने नई खेल नीति बनाने की घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए बजट में ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता की नगद ईनामी राशि को तीन करोड़ रुपए से पांच करोड़ रुपए, रजत पदक की दो करोड़ रुपए को तीन करोड़ रुपए व कांस्य पदक विजेता के एक करोड़ रुपए को दो करोड़ रुपए तक बढ़ाया है। एशियन व राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं के नगद ईनाम में भारी बढ़ोतरी कर एशियाड के स्वर्ण पदक विजेता के पचास लाख रुपए को चार करोड़ रुपए, रजत के बीस लाख रुपए को अढाई करोड़ रुपए व कांस्य पदक विजेता के बीस लाख रुपए को डेढ़ करोड़ तथा राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को तीन करोड़, रजत के लिए दो करोड़ रुपए व कांस्य पदक विजेता को एक करोड़ रुपए तक बढ़ा कर हिमाचल प्रदेश के खिलाडियों को बहुत बड़ी सौगात दी है।

जब विक्रमादित्य सिंह खेल मंत्री थे तो उन्होंने राज्य के लिए नई खेल नीति लाने की बात की थी, जिससे खिलाडियों को अधिक लाभ होगा, वह भी पूरा हो रहा है। दशक पूर्व जब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंतरराष्ट्रीय खेलों के पदाधिकारियों की ईनामी राशि को लाखों से करोड़ों में किया था, तो उसके बाद हरियाणा में खिलाडियों व उनके अभिभावकों ने अपने बच्चों का कैरियर खेलों में तलाशना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में ड्रिल व खेलों के लिए एक पीरियड, जो वर्षों पहले पढ़ाई के नाम पर खत्म कर दिया था, अब फिर से शुरू करने का क्रांतिकारी कदम उठाकर सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों की फिटनेस को ध्यान में रखने को तो जरूर कहा है, मगर वह धरातल पर कहीं भी दिख नहीं रहा है। सरकार ने स्कूली स्तर पर खिलाडियों के प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं के लिए समय सीमित कर दिया है, जो कथनी व करनी में बहुत फर्क दिखा रहा है। प्रतियोगिता व प्रशिक्षण शिविरों के समय खिलाडियों को खाने में बहुत दिक्कत रहती है। सरकार द्वारा खुराक भत्ता बढ़ाना हिमाचल प्रदेश की खेलों व खिलाडियों के लिए अच्छा संकेत है, मगर साथ ही साथ खिलाडियों के प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं के लिए उचित समय देकर खेलों के साथ न्याय करे।

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने राज्य में खेलों के लिए ऐतिहासिक फैसले लेकर खिलाडियों व खेल प्रेमियों को खुश कर दिया है, जैसे आशा थी कि जुलाई के उपचुनावों के बाद जल्दी ही प्रदेश के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल को गौरव दिलाने वाले पदाधिकारियों के लिए नगद ईनाम बांट समारोह का आयोजन सरकार द्वारा कर दिया जाएगा, वह भी हो रहा है। खिलाड़ी तो प्रशिक्षक ही बनाएगा। ओलंपिक 2036 भारत में आयोजित करवाने की बात हो रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस स्तर पर भारत का प्रदर्शन भी उत्कृष्ट हो। इसलिए भारत में अच्छे प्रशिक्षकों को सही सुविधा व प्रबंधन देना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि खिलाड़ी सें उच्च परिणाम केवल प्रशिक्षक ही दिलाता है, मगर कांग्रेस सरकार की इस ईनाम बढ़ोतरी में प्रशिक्षक को मिलने वाले नगद ईनाम पर चुप्पी क्यों है। आज का अभिभावक खेलों में भी अपने बच्चों का कैरियर देख रहा है, क्योंकि खेल आज अपने आप में एक प्रोफैशन है। मानव ने विज्ञान में बहुत प्रगति कर प्रौद्योगिकी व चिकित्सा के क्षेत्र में नए-नए सफल शोध कर जीवनशैली को काफी आसान व सुविधाजनक बना लिया है, मगर शिक्षण व प्रशिक्षण में शिक्षक व प्रशिक्षक की भूमिका का महत्व आज भी वही है, जैसा हजारों साल पहले था। महाभारत में कृष्ण सारथी नहीं होते, तो क्या अर्जुन भीष्म, कर्ण व अन्य अजेय महारथियों को हरा पाता? विश्व स्तर पर किसी खेल विशेष में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्षमतावान प्रशिक्षक का होना बेहद जरूरी होता है। आशा करते हैं कि सरकार प्रशिक्षकों को भी सम्मानजनक ईनामी राशि देगी।

सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि केवल खिलाडियों को ईनाम देने मात्र से हिमाचल में खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं की जा सकती। अन्य राज्यों में खिलाडियों के साथ-साथ प्रशिक्षकों के लिए भी नगद ईनाम की व्यवस्था है। तभी वे राज्य खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं। यह एक तथ्य है कि खिलाडियों को प्रशिक्षित करना, ताकि वे शानदार प्रदर्शन कर सकें, प्रशिक्षकों की ही जिम्मेदारी है। आजकल खेलों में प्रतिस्पर्धा कड़ी से भी कड़ी हो गई है। अतः खिलाडियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना निहायत ही जरूरी हो गया है। जहां तक हिमाचल की बात है, यहां पर कई प्रशिक्षक अपने स्तर पर खिलाडियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और सरकार की ओर से उन्हें विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सुविधाओं के अभाव में प्रशिक्षकों में निराशा पैदा होती है और वे मैदान से दूर होते चले जाते हैं। अगर हिमाचल को बेहतर खिलाड़ी चाहिएं, तो प्रशिक्षकों को ईनाम तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी ताकि वे आर्थिक रूप से निश्चिंत होकर अपना सारा समय खिलाडियों को प्रशिक्षित करने के लिए लगा सकें।

नाफावसूली और वैश्विक बिक्री के चलते 738 अंक लुढ़का सेंसेक्स, इन कंपनियों के शेयर गिरे

परिवहन विशेष न्यूज

बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 738.81 अंक की गिरावट के साथ 81 हजार के स्तर से नीचे गिरकर 80604.65 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 269.95 अंक की गिरावट के साथ 24530.90 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि बजट से पहले निवेशक सतर्कता बरतते हुए लगातार मुनाफावसूली भी कर रहे हैं।

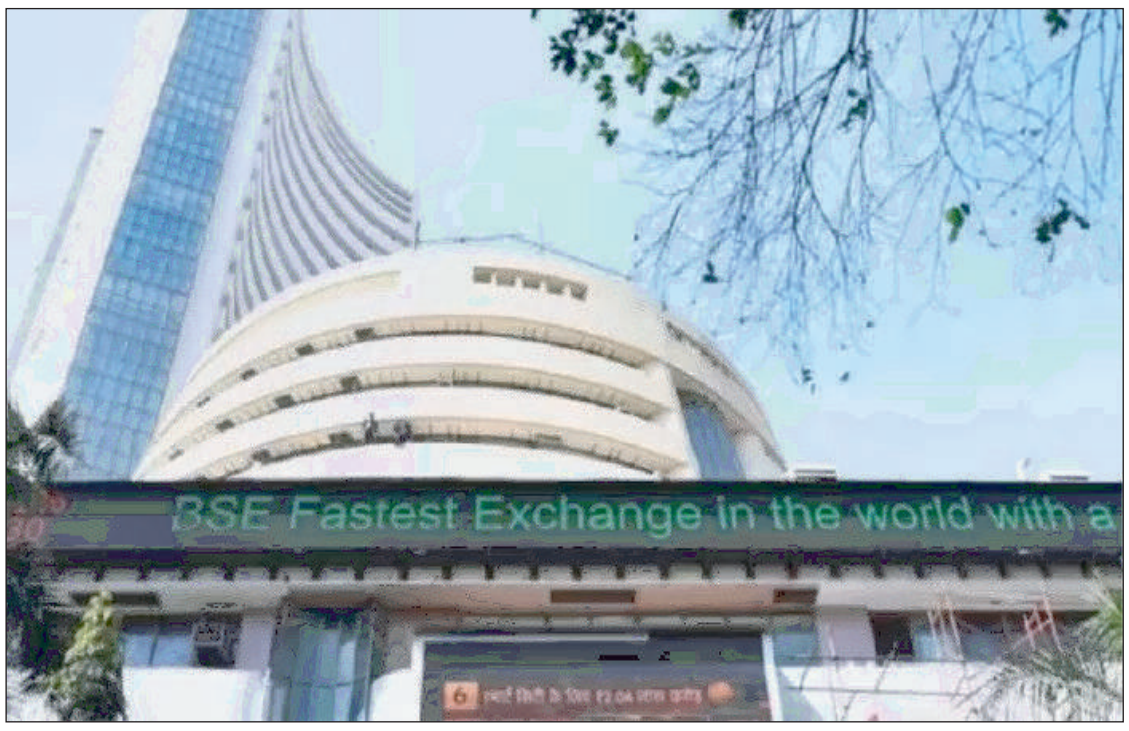

नई दिल्ली। मुनाफावसूली और तकनीकी दिक्कतों के कारण वैश्विक स्तर पर हुई बिक्री के चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार चार दिनों की तेजी के बाद शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए।

बाजार की मौजूदा स्थिति

बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 738.81 अंक की गिरावट के साथ 81 हजार के स्तर से नीचे गिरकर 80,604.65 अंक पर बंद हुआ। हालांकि, शुरुआत में यह 81,587.76 अंक के उच्च स्तर तक पहुंचा था।

इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 269.95 अंक की गिरावट के साथ 24,530.90 अंक पर बंद हुआ। आईटी आउटेज से कई ब्रोकरेज फर्मों के शेयरों में गिरावट देखी गई। बीएसई में एंजल वन के शेयर 3.42 प्रतिशत, 5पैसा कैपिटल के शेयर 3.15 प्रतिशत, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर 2.25 प्रतिशत, मोतीलाल ओसवाल 2.19 प्रतिशत और आइआइएफएल सिक्युरिटीज के शेयर 1.04 प्रतिशत गिरकर बंद हुए।

क्यों आई एकदम से गिरावट?

बाजार के जानकारों का कहना है कि बजट से पहले निवेशक सतर्कता बरतते हुए मुनाफावसूली भी कर रहे हैं। सेंसेक्स में टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में करीब पांच प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।

इन कंपनियों के गिरे शेयर

टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी गिरकर बंद हुए। इस गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में 7.94 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। अब बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटकर 446.38 लाख करोड़ रुपये या 5.34 ट्रिलियन डालर रह गया है। इससे पहले लगातार चार सत्रों में बीएसई में 1,446.12 अंकों की बढ़ोतरी हुई थी।

भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी से कैसे भरी उड़ान, RBI गर्वनर ने दिया जवाब

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि केंद्रीय बैंक पूरी तरह आश्वस्त है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 7.2 प्रतिशत का आर्थिक विकास दर का अनुमान पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति का ध्यान साफ और स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने बैंक से कर्ज-जमा वृद्धि के बीच बढ़ रहे फासले पर सतर्क रहने को कहा और सलाह दी कि ऋण को जमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

मुंबई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि उनके लगभग छह साल के कार्यकाल के दौरान सरकार के साथ केंद्रीय बैंक के संबंध अच्छे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के तेजी से पुनरोद्धार की एक बड़ी वजह यह भी थी कि दोनों के बीच घनिष्ट समन्वय रहा।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नौकरशाह से केंद्रीय बैंकर बने दास ने कहा किसी ने भी उनसे अपने कार्यकाल के दौरान सरकार के लिए चीयरलीडर बनने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा, 'मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि कोई भी यह उम्मीद नहीं करता है कि आरबीआई चीयरलीडर बने। मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है।'

दास उस सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उनके पूर्ववर्ती ने अपनी किताब में यह आरोप लगाया था कि सरकार चाहती है कि आरबीआई उसके मुताबिक काम करे। आरबीआई गवर्नर के तौर पर एक और कार्यकाल मिलने के बारे में पूछे गए सवाल पर दास ने कहा, 'अभी मेरा पूरा ध्यान वर्तमान के कामकाज पर है इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोचता हूं।'

दास ने कहा कि आरबीआई पूरी तरह आश्वस्त है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 7.2 प्रतिशत का आर्थिक विकास दर का अनुमान पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति का ध्यान साफ और स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने बैंक से कर्ज और जमा वृद्धि के बीच बढ़ रहे फासले पर सतर्क रहने को कहा और सलाह दी कि ऋण को जमा से अधिक नहीं होना चाहिए। दास ने कहा कि असुरक्षित कर्ज पर आरबीआई की कार्रवाई का प्रभाव पड़ा है, लेकिन कुछ बैंकों द्वारा असुरक्षित कर्ज बांटे पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की।

कारोबारी घरानों को रियायत देने की योजना नहीं

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक के पास फिलहाल कारोबारी घरानों को बैंक खोलने की मंजूरी देने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि कारोबारी घरानों को बैंक चलाने की अनुमति देने से हितों के टकराव और संबंधित पक्षों के लेनदेन से जुड़ा जोखिम बढ़ जाता है।

आरबीआई ने लगभग एक दशक पहले बैंकों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया के अंतिम दौर में कई बड़े कारोबारी समूहों को नए बैंकों का लाइसेंस देने के अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि देश की वृद्धि आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने की कारोबारी घरानों की क्षमता को देखते हुए आरबीआई के एक कार्य समूह ने वर्ष 2020 में इस मुद्दे पर नए सिरे से चर्चा शुरू की थी।

एनआरआई ने भरा भारत का खजाना, अप्रैल-मई के दौरान चार गुना बढ़ा बैंक डिपॉजिट

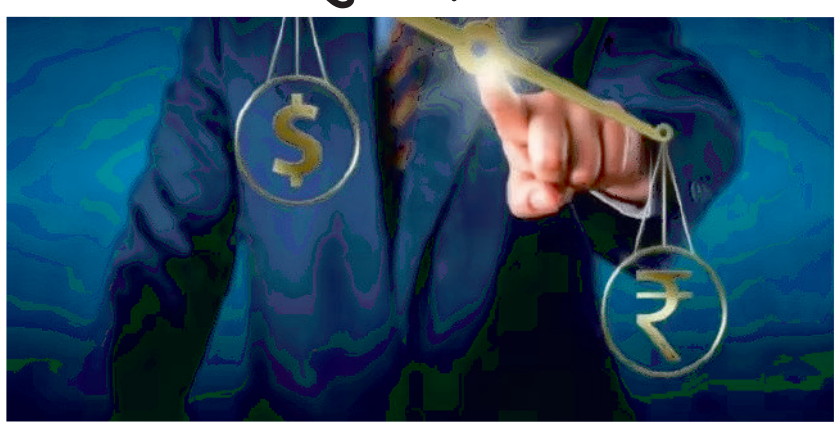

आरबीआई के डेटा के अनुसार अप्रैल-मई के दौरान एनआरआई जमा 2.7 अरब डॉलर रही है। यह पिछले वर्ष समान अवधि में 0.6 अरब डॉलर थी। बैंक जमा बढ़ने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिल रही है। एनआरआई की कुल जमा मई में बढ़कर 154.72 अरब डॉलर हो गई है। बड़ी मात्रा में होने वाली इस जमा से रुपये को भी सहारा मिलता है।

नई दिल्ली। विदेशी में काम करने वालों यानी अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की ओर से बैंक जमा इस वर्ष अप्रैल-मई के दौरान चार गुना बढ़ी है। आरबीआई के डेटा के अनुसार, इस दौरान एनआरआई जमा 2.7 अरब डॉलर रही है जो पिछले वर्ष समान अवधि में 0.6 अरब डॉलर थी। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिल रही है।

एनआरआई की कुल जमा मई में बढ़कर 154.72 अरब डॉलर हो गई है। बड़ी मात्रा में होने वाली इस जमा से रुपये को भी सहारा मिलता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख मुद्राओं में रुपया सबसे अधिक स्थिर मुद्रा के रूप में उभरा है।

पांच जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 657.16 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा है। यह अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियादी बातों को दर्शाता है और आरबीआई को रुपये को स्थिर करने के लिए अधिक गुंजाइश देता है।

जून तिमाही में 12 फीसदी बढ़ा रिलायंस का रेवेन्यू, मुकेश अंबानी बोले- देश की तरक्की में अहम

परिवहन विशेष न्यूज

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के कंसालिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि ऑपरेशन से रेवेन्यू में सालाना आधार पर 12 फीसदी का तगड़ा उछाल आया है और यह समीक्षाधीन अवधि में 2.36 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन इसके विविध पोर्टफोलियो के कारोबार की ताकत को दर्शाता है।

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के कंसालिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून के दौरान यह 15,138 करोड़ रुपये रहा। वहीं, एक साल पहले की समान अवधि में यह 16,011 करोड़ रुपये थी।

हालांकि, ऑपरेशन से रेवेन्यू में सालाना आधार पर 12 फीसदी का तगड़ा उछाल आया है और यह समीक्षाधीन अवधि में 2.36 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। नेट प्रॉफिट के मामले में यह एनालिस्टों के अनुमान पर खरी नहीं उतरी। एनालिस्टों का मानना था कि जून तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 16,341 करोड़ रुपये रह सकता है। लेकिन, रेवेन्यू के लिहाज से अनुमान सटीक रहे।

अगर कंसालिडेटेड EBITDA की बात करें, तो यह पहली तिमाही में सालाना आधार पर 2 फीसदी बढ़कर 42,748 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, EBITDA मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट्स साल दर साल के हिसाब से 16.6 फीसदी पर आ गया।

रेवेन्यू में कैसे आया तगड़ा उछाल?

रिलायंस इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू में तगड़े उछाल की अगुआई O2C सेगमेंट ने की। खासकर, ऑयल और गैस की ऊंची कीमतों और अच्छी बिक्री के चलते कंपनी को काफी फायदा मिला। कंज्यूमर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ रही, जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज को रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिली। रिलायंस का ओवरऑल प्रदर्शन काफी बेहतर रहा।

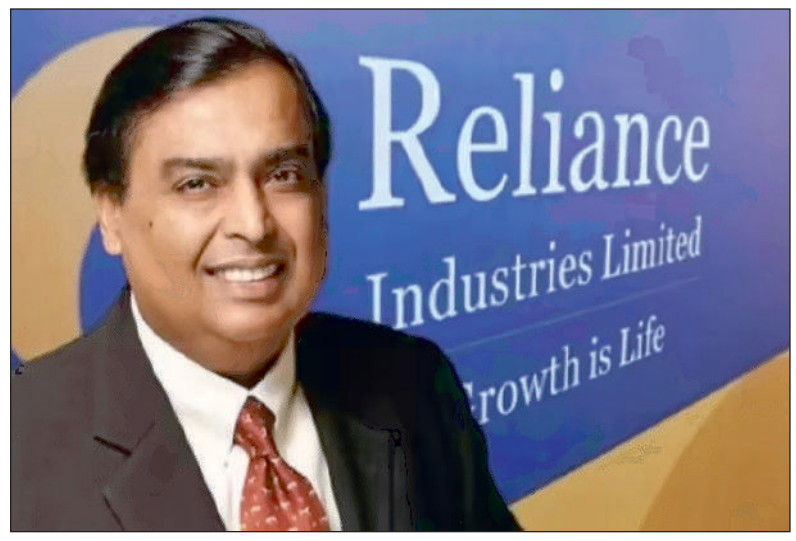

इस तिमाही में रिलायंस का मजबूत परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन इसके विविध पोर्टफोलियो के कारोबार की ताकत को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कारोबार भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वस्तुओं और सेवाओं के डिजिटल और भौतिक वितरण के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा और जीवंत चैनल प्रदान कर रहे हैं।

मुकेश अंबानी, एमडी और चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज

इक्रोसॉफ्ट आउटेज से भारत के 10 बैंक प्रभावित कई देशों के स्टॉक मार्केट और एटीएम रहे ठप

अमेरिकी टेक कंपनी का सर्वर पूरी दुनिया में ठप हो गया है। इसके चलते एयरलाइंस से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों का कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कई देशों में स्टॉक एक्सचेंज और बैंक का कामकाज भी बाधित है। लोगों को एटीएम से पैसे निकालने में भी परेशानी हो रही हैं। आइए जानते हैं कि भारत के स्टॉक मार्केट और बैंकों पर भी क्या असर हुआ है।

नई दिल्ली। अमेरिकी टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप (Microsoft outage) से दुनियाभर की कई बड़ी कंपनियों का कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। कई देशों में बहुत-सी एयरलाइंस को संचालन में दिक्कत आ रही है। स्टॉक एक्सचेंजों और बैंकों का कामकाज बाधित हुआ। भारत में भी इंडिगो और अकासा एयरलाइंस जैसी विमानन कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ है। लेकिन, शेयर मार्केट और बैंकों का कामकाज अभी तक सुचारू रूप से जारी है।

NSE बोला, हम पर असर नहीं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का कहना है कि उस पर माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में तकनीकी खराबी का कोई असर नहीं हुआ है, जिससे दुनिया के कई देशों के शेयर मार्केट प्रभावित हैं। NSE का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग सुचारू रूप से जारी है।

हालांकि, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म को परेशानी हो रही है। नुवामा, 5पैसा और IIFL सिक्योरिटीज सहित कुछ अन्य ब्रोकरेज हाउस की सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से प्रभावित हुई है। इन्वेस्टर खरीदने और बेचने के लिए सौदे नहीं लगा पा रहे हैं।

SBI का कामकाज भी जारी

अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों के बैंक भी माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से प्रभावित हुए हैं। लेकिन, भारत के सबसे बड़े बैंक- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) इस समस्या से पूरी तरह से अछूता है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने ग्लोबल आउटेज से जुड़े सवाल पर कहा, 'हमारा सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त है और हमें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।'

बैंकिंग RBI ने भी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का देश के फाइनेंशियल और पेमेंट सिस्टम पर कोई असर नहीं दिखा। हालांकि, 10 बैंक और NBFC कुछ हद तक वैश्विक आउटेज से प्रभावित रहे। लेकिन, उनकी समस्या को जल्द ही दूर कर लिया गया।

माइक्रोसॉफ्ट में क्या दिक्कत हुई?

माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। इसके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम- विंडोज का इस्तेमाल आम लोगों से लेकर दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों के दफ्तरों में होता है। लेकिन, शुक्रवार को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर और लैपटॉप अचानक से रीस्टार्ट और शटडाउन होने लगे।

इससे दुनियाभर के यूजर्स को परेशानी हुई। कुछ यूजर्स को लैपटॉप पर नीली स्क्रीन दिखाई दे रही है। डेल टेक्नोलॉजीज का कहना है कि यह परेशानी हालिया क्राउडस्ट्राइक अपडेट के कारण हुई है। CrowdSrike एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। यह यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है।

समस्या का व्यापक असर

माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी से दुनियाभर में एयरलाइंस, टीवी टेलिकास्ट, बैंकिंग और कई कार्पोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है। भारत समेत दुनियाभर में एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही है। कई उड़ानों में या तो देरी हो रही है, या फिर उन्हें रद्द किया जा रहा है।

कब तक बहाल होंगी सेवाएं?

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसे समस्या की जानकारी है और वह इसे युद्ध स्तर पर सुलझाने में लगी हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए कई टीमों को लगा रखा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने समस्या की वजह पता लगा ली है और कुछ सेवाओं को इसने वापस बहाल भी कर दिया है। क्राउडस्ट्राइक के अपडेट के चलते सबसे अधिक माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज के यूजर परेशान हैं।

Byju's की दिवालिया कार्यवाही नहीं रुकी, तो हजारों कर्मचारियों को नौकरी से धोना पड़ेगा हाथ

निवेशकों ने सीईओ बायजू रवींद्रन पर कारपोरेट प्रशासन में चूक का आरोप लगाया है। हालांकि कंपनी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। अगर Byjus के खिलाफ शुरू हुई दिवालिया कार्यवाही नहीं रोकी गई तो न केवल हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं भी पूरी तरह बंद हो जाएंगी।

नई दिल्ली। एडटेक कंपनी Byju's ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अगर उसके खिलाफ शुरू की गई दिवालिया कार्यवाही नहीं रोकी गई, तो न केवल हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं भी पूरी तरह बंद हो जाएंगी।

Byju's ने दी सफाई

प्रोसस और जनरल अटलांटिक जैसे निवेशकों द्वारा सपोर्टेड Byju's को हाल के महीनों में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसमें नौकरी में कटौती, कंपनी के मूल्यांकन में गिरावट और निवेशकों के साथ झगड़ा शामिल है।

BCCI की याचिका स्वीकारी गई

निवेशकों ने सीईओ बायजू रवींद्रन पर कारपोरेट प्रशासन में चूक का आरोप लगाया है। हालांकि, कंपनी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। कंपनी की ताजा दिक्कत उस समय शुरू हुई जब नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (NCLT) ने उसके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की याचिका स्वीकार कर ली।

ये मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजूस और बीसीसीआइ के बीच स्पॉन्सरशिप समझौते से जुड़ा है। बीसीसीआइ ने 158.9 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पिछले साल याचिका दायर की थी। इसके खिलाफ बायजूस ने एनसीएलएटी में याचिका दायर की है। बायजूस की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं और उसके बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है।

बस कंडक्टर टिकट देते समय उसे बीच से क्यों फाड़ देते हैं?

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में DTC बसों में सफर करते हुए, क्या आपने कभी गौर किया है कि कंडक्टर टिकट देते समय उसे बीच से क्यों फाड़ देते हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं तो आप हम इसके पीछे की कहानी बताने वाले हैं। आइए जानते हैं कंडक्टर क्यों करते हैं ऐसा

नई दिल्ली: बस हो या ट्रेन उसमें सफर के लिए सबसे जरूरी होता है टिकट। अगर आपके पास टिकट है तो ही आप बस और ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। अन्यथा आपको पेनल्टी लग सकती है। ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट काउंटर से टिकट लेना होता है लेकिन अगर आप बस में सफर कर रहे हैं तो आपको बस कंडक्टर से टिकट लेना पड़ता है। अगर आपने कभी दिल्ली की DTC बसों में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि टिकट देते वक्त कंडक्टर टिकट को कभी-कभी बीच में से फाड़ देता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर बस कंडक्टर ऐसा क्यों करता है। चलिए आज हम आपको इसके पीछे की कहानी बताने वाले हैं।

दिल्ली डीटीसी बस टिकट

दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से दो तरह की बसें चलती है एक AC और दूसरी नॉन AC यानी साधारण बस। अगर आप साधारण बस में सफर करते हैं तो उसका किराया 10 और 15 रुपये होता है। जबकि AC वाली बसों का किराया 25 तक चला जाता है। अगर आप शुरुआत से अंत तक सफर करते हैं तो आपको साधारण बस में 15 और AC बसों में 25 रुपये का टिकट खरीदना होगा। अगर आप बीच में उतरते हैं तो साधारण बस में 10 रुपये और AC बसों में 10,15 और 25 होता है। ये किराया किलोमीटर के हिसाब से पहले ही तय किया जा चुका है। उसी के अनुसार कंडक्टर टिकट के पैसे लेता है।

कंडक्टर क्यों फाड़ता है टिकट

कई बार लोग 10 रुपये का टिकट लेकर बस में आगे तक सफर करते हैं। ऐसे ही लोगों की पहचान करने के लिए टिकट कंडक्टर आपको टिकट देने से पहले पूछता है कि आप कहां तक जाएंगे। आप जिस स्टैंड का नाम बताते हैं उस हिसाब से कंडक्टर टिकट को फाड़ देता है। जिससे बाद में कभी चेकिंग के दौरान पता रहे कि कोई कम दूरी का टिकट खरीदकर आगे तक तो सफर नहीं कर रहा है। इसलिए बस कंडक्टर टिकट को आपके द्वारा बताए गए स्टेशन के आसपास से फाड़ देता है।

इसके साथ ही कई बार आपने देखा होगा कि बस कंडक्टर के पास पंचिंग मशीन होती है। जिसकी मदद से वो आपके द्वारा बताए गए स्टैंड को क्रम (टिकट पर दिए गए नंबर 1,2,3,4,5,6,7,8,9...) के अनुसार पंच करके उसमें छेद कर देता है। जिससे कंडक्टर को पता हो कि यात्री ने कहां तक की टिकट ली है।

ऑल इंडिया मीडिया क्लब देश को समर्पित करता है प्रति वर्ष लाखों पेड़: मीडिया चेयरमैन।

सुषमा रानी ।दिल्ली। पत्रकारों की संस्था ऑल इंडिया मीडिया क्लब रजिस्टर्ड द्वारा हर साल देश भर में पत्रकार बंधुओं की संस्था पौधारोपण करके राष्ट्र की धरती को हरा भरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पौधारोपण का कार्य पूरे देश में तेजी के साथ चल रहा है आज ऑल इंडिया मीडिया क्लब के अध्यक्ष डॉ० एम० क्यू० मलिक ने अपने साथियों के साथ हरिद्वार उत्तराखंड के समीप फैक्ट्रीयों मैं शोभाकर छायादार फलदार के अलावा औषधीय पौधों का पौधारोपण किया गया क्लब द्वारा पौधे लगाने के लिए ऐसी जगह को चिन्हित किया जाता है जहां उसकी परवरिश हो सके इसीलिए क्लब द्वारा पौधों को मूल रूप से फैक्ट्री स्कूल कॉलेज शमशानघाट कब्रिस्तान मद्रासियों धर्मशालाओं और सरकारी कार्यालयों के आहातों मैं लगाए जाते हैं। पिछले सालों में लगाए गए पेड़ों को जब हरा भरा फलता फूलता देखते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। मीडिया चेयरमैन ने बताया पौधारोपण का कार्य प्रगति पर चल रहा है जो देशभर में अभी बिना रुके चलता रहेगा। तमाम पत्रकार साथियों से अपील की गई है कि वह पिछले साल की अपेक्षा में इस बार अपने अथक प्रयास से और ज्यादा पेड़ लगवाने का प्रयास करें क्योंकि हीट वेव पर कंट्रोल और ऑक्सीजन की कमी पर हम पर्यावरण के माध्यम से ही विजय पा सकते हैं जिससे हमारा देश और देश की जनता अमूल्य जीवन मिलता रहेगा।

सुधांसु सरगी पुलिस DGP बन सकते

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेश्वर : यात्रा समाप्त हो गई है । बजट सत्र अगले सप्ताह आयोजित किया जाएगा । इसके बीच राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में एक बड़े बदलाव ने हलचल मचा दी है । स्वाभाविक रूप से, जब सरकार बदलती है, तो आईएएस, आईपीएस स्तर पर पार्टियाँ बदल जाती हैं। नई सरकार के गठन के बाद रथ यात्रा और बजट सत्र के कारण विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों की सूची जारी नहीं की गई है ।ऐसे में जल्द ही आईपीएस लेयर में बड़े बदलाव की झलक मिल रही है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है कि जल्द ही स्पष्ट तस्वीर मिलने की संभावना है ।

इस सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक आईपीएस एक्सचेंज को लेकर फैसला फाइनल हो चुका है । इस संबंध में कुछ और विचार-विमर्श बाकी है और हरी झंडी मिलने के बाद वैधानिक अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी।

बताया जा रहा है कि दोहरे शहर पुलिस आयुक्त संजीव पांडा, कटक और भुवनेश्वर डीसीपी को बदला जा सकता है। सरकार इस पद पर अपनी पसंद के अधिकारी को नियुक्त करना चाहती है, भले ही सीपी श्री पांडा को बदला नहीं गया है । इसके साथ ही एडीजी स्तर के अधिकारी भी बदले जायेंगे । इस सूत्र के अनुसार, पुलिस निदेशक, सतर्कता निदेशक, एडीजी कानून प्रवर्तन, एडीजी यातायात सहित दक्षिण, पूर्व, उत्तर, दक्षिण पश्चिम के पुलिस प्रमुखों को बदल दिया जाएगा। इसके मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि गृह विभाग में कार्यरत कुछ आईपीएस को अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकता है ।

मुख्य सासन सचिब एक नॉन ओड़िआ हुआ है इसीलिए बीजेपी बैकफुट पर है , क्वू की बीजेपी ओड़िआ अस्मिता पर चुनाब लड़ा ओर फिर जिता । मुख्य सासन सचिब नियुक्ति को लेके बिरोधी बिधान सभा मे प्रसंग करेंगे । ओड़िआ अस्मिता का प्रश्न । इसीलिए कोई भी ओड़िआ पुलिस DGP बनेगे । अरुण सरगी अबी DGP इंचार्ज है , इन को नबीन पटनायक की सरकार मे नियुक्ति मिला ।लेकिन सुधांसु सरगी को बिजेड़ी सरकार मे पुलिस कमिशनर अलाबा ओर कुछ अच्छा नियुक्ति नहीं मिली । सुधांसु सरगी बिजेड़ी सरकार की गुडबुक मे नहीं थे । सुधांसु सरगी पुलिस DGP बन सकते ।

भुबनेश्वर : यात्रा समाप्त हो गई है । बजट सत्र अगले सप्ताह आयोजित किया जाएगा । इसके बीच राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में एक बड़े बदलाव ने हलचल मचा दी है । स्वाभाविक रूप से, जब सरकार बदलती है, तो आईएएस, आईपीएस स्तर पर पार्टियाँ बदल जाती हैं। नई सरकार के गठन के बाद रथ यात्रा और बजट सत्र के कारण विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों की सूची जारी नहीं की गई है ।ऐसे में जल्द ही आईपीएस लेयर में बड़े बदलाव की झलक मिल रही है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है कि जल्द ही स्पष्ट तस्वीर मिलने की संभावना है ।

इस सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक आईपीएस एक्सचेंज को लेकर फैसला फाइनल हो चुका है । इस संबंध में कुछ और विचार-विमर्श बाकी है और हरी झंडी मिलने के बाद वैधानिक अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। बताया जा रहा है कि दोहरे शहर पुलिस आयुक्त संजीव पांडा, कटक और भुवनेश्वर डीसीपी को बदला जा सकता है। सरकार इस पद पर अपनी पसंद के अधिकारी को नियुक्त करना चाहती है, भले ही सीपी श्री पांडा को बदला नहीं गया है । इसके साथ ही एडीजी स्तर के अधिकारी भी बदले जायेंगे । इस सूत्र के अनुसार, पुलिस निदेशक, सतर्कता निदेशक, एडीजी कानून प्रवर्तन, एडीजी यातायात सहित दक्षिण, पूर्व, उत्तर, दक्षिण पश्चिम के पुलिस प्रमुखों को बदल दिया जाएगा। इसके मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि गृह विभाग में कार्यरत कुछ आईपीएस को अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकता है ।

मुख्य सासन सचिब एक नॉन ओड़िआ हुआ है इसीलिए बीजेपी बैकफुट पर है , क्वू की बीजेपी ओड़िआ अस्मिता पर चुनाब लड़ा ओर फिर जिता । मुख्य सासन सचिब नियुक्ति को लेके बिरोधी बिधान सभा मे प्रसंग करेंगे । ओड़िआ अस्मिता का प्रश्न । इसीलिए कोई भी ओड़िआ पुलिस DGP बनेगे । अरुण सरगी अबी DGP इंचार्ज है , इन को नबीन पटनायक की सरकार मे नियुक्ति मिला ।लेकिन सुधांसु सरगी को बिजेड़ी सरकार मे पुलिस कमिशनर अलाबा ओर कुछ अच्छा नियुक्ति नहीं मिली । सुधांसु सरगी बिजेड़ी सरकार की गुडबुक मे नहीं थे । सुधांसु सरगी पुलिस DGP बन सकते ।

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टाफ भर्ती में भी एनटीए ने कर दी बडी धांधली,इस पर डीयू मौन,एक्शन में डीयू यूनियन

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। नेशनल टेस्ट- एजेंसी (एनटीए) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी भर्ती के नाम पर आवेदन कर्ताओ के करीब 40-50 करोड रूपये, डकार लिए है। इस बावत एनटीए ने अब तक ना तो आवेदकों की परीक्षा ही ली और ना ही उनसे ली गई रकम ही लौटाई। हद तो तब हो गई जब एनटीए की ओर से आज-तक भी कोई सूचना देने की जुर्रत तक नहीं समझी गई। हालत ये है कि 4-5 लाख की संख्या में 1145 कैडर्स के लाखों प्रार्थी बेफकूफ बनकर एनटीए की ओर मुंह ताक रहे है। इस बावत दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन प्रेसीडेंट देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि एनटीए की धांधली के मारे लाखो आवेदन कर्ता अपनी नौकरी के इंतजार में पिछले तीन साल से एनटीए से आस लगाए बैठे है। लेकिन एनटीए समेत डीयू प्रशासन मौन साधे हुए है। प्रेसीडेंट शर्मा के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी में गैर शिक्षण 1145 कैडर्स की भर्ती नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा साल 2021 में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। इसके लिए करीब 4 से 5 लाख की संख्या में अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन किए गए। प्रत्येक- अभ्यार्थियों से आवेदन के साथ बाकायदा 1000 रूपये की राशि भी ली गई। 5 लाख आवेदकों से प्रत्येक से 1000 रूपये के हिसाब से ये कुल राशि 50 करोड रूपये की मोटी रकम बनती है। प्रेसीडेंट देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि इस बारे में यूनियन द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन, समेत एनटीए के भी संज्ञान में लाने के बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और एनटीए तक चुप्पी साधे बैठे है। पिछले तीन साल की इंतजार की घडियां खत्म हुई, तो हारकर इस बावत यूनियन ने यूजीसी, शिक्षा मंत्री, समेत सीबीआई तक को पत्र लिखकर इस करोडों रूपये की धांधली पर संज्ञान लेने को पत्र लिखा। यूनियन प्रेसीडेंट देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि इस बावत यूनियन के पत्र दिनांक 25 जून,2024 के जवाब में पत्रांक संख्या 35/2012/सीयू/फाइल/ 11/10278 तिथि 8 जुलाई, 2024 यूजीसी के अंडर सेकेट्री लोकेश कुमार जांगडा द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र भेजा गया है। पत्र मे लिखा गया है कि यूजीसी ने आपके द्वारा प्रेषित पत्र से संबंधित कन्टेंट को संबंधित अथॉरटी को सूचित कर दिया है।

पटना मेट्रो रेल 2025 तक हो जाएगी चालू! जानें स्टेशनों और रूट की पूरी डिटेल्स

बिहार की राजधानी पटना के निवासी जल्द ही खुश हो सकते हैं। क्योंकि शहर अगले साल अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। इस कॉरिडोर के साथ स्टेशनों का निर्माण वर्तमान में चल रहा है, जिसमें पिलरों को लगाने के काम में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। जानें डिटेल्स।

पटना। बिहार की राजधानी पटना के निवासी जल्द ही खुश हो सकते हैं। क्योंकि शहर अगले साल अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। इसका पहला रूट, बैरिया बस टर्मिनल से मालाही पाकड़ी तक, एक ऊंचे ट्रैक पर 6.4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। जिससे हजारों निवासियों के लिए आने-जाने की समस्या कम हो जाएगी। इस कॉरिडोर के साथ स्टेशनों का निर्माण वर्तमान में चल रहा है, जिसमें पिलरों को लगाने के काम में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। शहरी विकास मंत्री नितिन नवीन ने शेष बुनियादी ढांचे को समय पर पूरा करने के लिए तेजी से प्रयास करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है।

पटना मेट्रो की खास बातें

रूट और स्टेशन

पटना मेट्रो का पहला परिचालन खंड, जिसे कॉरिडोर दो के नाम से जाना जाता है, में पांच ऊंचे स्टेशन शामिल होंगेः पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरो माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मालाही पाकड़ी। कुल 6.63 किलोमीटर में फैला यह खंड यात्रियों के लिए निर्बाध संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा।

क्या है प्रोजेक्ट

व्यापक पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें दो कॉरिडोर शामिल हैं, कुल 24 स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इनमें 12 भूमिगत (अंडरग्राउंड) और 12 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। जो पूरे शहर में अर्बन मोबिलिटी (शहरी गतिशीलता) को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित हैं।

कॉरिडोर डिटेल्स

कॉरिडोर-1 17.93 किलोमीटर में फैला है, जिसमें 7.39 किलोमीटर एलिवेटेड और 10.54 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। कॉरिडोर-2, शुरुआती कार्यों का केंद्र बिंदु, 14.55 किलोमीटर को कवर करता है, जिसमें 6.63 किलोमीटर एलिवेटेड और 7.92 किलोमीटर अंडरग्राउंड शामिल है।

पटना मेट्रो की शुरुआत शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जो इसकी बढ़ती आबादी के लिए तेज, ज्यादा कुशल यात्रा विकल्प का वादा करता है। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ने के साथ, मेट्रो नेटवर्क आने वाले वर्षों में पटना में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन (शहरी परिवहन) को बदलने के लिए तैयार है।

मंगोल पुरी में देश का सबसे बडा ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार सितंबर में उद्घाटन

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

राजधानी दिल्ली के मंगोल पुरी स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल परिसर में देश का सबसे बडा 9 मंजिला ट्रामा सेंटर इलाज के लिए बन कर तैयार है। 84 करोड रूपये की लागत से तैयार होने वाला ये ट्रॉमा सेंटर पौने दो साल में बनना था। लेकिन लेट लतीफी के चलते अब इसकी लागत बढकर 117.78 करोड हो गई है। 9 मंजिला ट्रामा सेंटर में 362 बेड्स, और 39 आईसीयू होगें। इसमें बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा दी गई है। 362 बेड्स में से 50 फीसदी बेड्स इमर्जेंसी एक्सीडेंटल केस केयर विद आईसीयू के साथ होगें। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यू महकमें के आलाधिकारियो के मुताबिक संजय गांधी ट्रामा सेंटर का सिविल व इलैक्ट्रिकल का काम पूरा हो गया है। सितंबर में इसका उद्घाटन होगा। उल्लेखनीय है कि इस ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य सितंबर,2019 में शुरू किया गया था। और मार्च, 2021

तक कंप्लीट होना था। बीच में कोरोना महामारी के चलते काम में बाधाए आई। लेकिन अब सितंबर की डेडलाइन, फाइनल है। बता दें कि राजधानी दिल्ली का सबसे पहला ट्रामा सेंटर 1998 में लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) अस्पताल में सुश्रुत ट्रामा सेंटर बनाया था। इसमें 49 बेड्स है। इसके बाद 2006 में एम्स अस्पताल में जेपी ट्रामा सेंटर शुरू हुआ। इसमें कुल बेड्स क्षमता 243 है। इनमें से 232 जनरल और 11 प्राइवेट बेड है। इसमें 5 आप्रेशन थिएटर है और करीब 30 आईसीयू बेड है। इसके बाद 2008 में , आरएमएल(राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रामा सेंटर शुरू किया। 6 मंजिले इस ट्रामा सेंटर में 78 बेड्स है। 3 आप्रेशन थिएटर, 11 आईसीयू बेड्स है। बाद में चंदगी राम अखाडा के पास ट्रामा सेंटर है। लेकिन दिल्ली के तमाम ट्रामा सेंटर में मंगोल पुरी संजय गांधी ट्रामा सेंटर सबसे बडा है। उल्लेखनीय है की दिल्ली सरकार ने 2009 में 15 सरकारी अस्पतालों के विस्तार की योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए बाकायदा 2029 करोड रूपये की लागत से अस्पतालों का विस्तार करके उनमें करीब 17 हजार बेड्स बढाए जाने थे। 11 और न ए अस्पताल का निर्माण भी होना था। मगर अब यूएसबी परियोजनाए अपनी तय डेडलाइन से तीन से चार साल पीछे चल रही है। गडबडियों की बढती शिकायतों के चलते कंस्ट्रक्शन के लिए एजेंसियों के परमिशन मिलने में अडंगे जैसे कारणो से मरीजों को मिलने वाली तमाम स्वास्थ्य सुविधाओ से वंचित हो रहे है।

जलवायु परिवर्तन, हरित संक्रमण और स्थिरता पर अंत:विषय केंद्र पर बैठक आयोजित की

सुषमा रानी

नईदिल्ली। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय ने अपने मैदान गढ़ी परिसर में जलवायु परिवर्तन, हरित संक्रमण और स्थिरता पर प्रस्तावित अंत:विषय केंद्र की पहली बैठक आयोजित की। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण और स्थिरता जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक समर्पित अंत:विषय केंद्र की आवश्यकता है।

दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव गंभीर हैं, जो जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित करते हैं और इसके लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए प्रभावी अनुकूलन रणनीतियों, उपकरणों, कौशल और सहयोगी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। सीमाओं के पार ज्ञान नेटवर्क बनाने के अधिदेश के साथ, जलवायु परिवर्तन, हरित संक्रमण और स्थिरता पर अंत:विषय केंद्र को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य ज्ञान नेटवर्क बनाना और शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, चिकित्सकों, विचारकों और परिवर्तन निर्माताओं को एक साथ लाना है। एसएयू के अध्यक्ष प्रोफेसर के के अग्रवाल की अध्यक्षता में, शिक्षाविदों, नीति चिकित्सकों और उद्यमियों की उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ी। अपने भाषण के दौरान, प्रो. के के अग्रवाल ने रेखांकित किया कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की परिकल्पना अत्याधुनिक शैक्षणिक, अनुसंधान और तकनीकी केंद्र के लिए एक स्थान के रूप में की गई थी, जो क्षेत्र में उपलब्ध सामूहिक संसाधनों का उपयोग करके साझा समृद्धि को बढ़ावा दे और सद्भाव को बढ़ावा दे। प्रस्तावित केंद्र उस दिशा में एक कदम आगे है। उन्होंने कहा कि विकास और स्थिरता हमारे समाज में एक साथ रह सकते हैं, और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान खोजने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं। केंद्र का संदर्भ निर्धारित करते हुए, मॉरीशस में भारत के पूर्व उच्चायुक्त राजदूत अनूप के मुदगल ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आसन्न जोखिम को रेखांकित किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के उन समाधानों पर सवाल उठाने के लिए वैश्विक दक्षिण की आवश्यकता पर जोर दिया जो इन देशों के लिए जरूरी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि समाधान अलग-अलग नहीं हो सकते और वैश्विक दक्षिण को अपनी क्षमता का निर्माण करना होगा तथा जलवायु परिवर्तन और स्थिरता से संबंधित कठिन सवालों के सही जवाब खोजने का प्रयास करना होगा।

केंद्र की समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर पूरन चंद्र पांडे ने प्रस्तावित केंद्र पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें केंद्र द्वारा किए जाने वाले परिचालन मॉडल, फंडिंग पैटर्न, गतिविधियों और पहलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

विशेषज्ञों और विशेष आमंत्रितों ने केंद्र के बारे में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, जिसमें इसका नामकरण, परिचालन मॉडल, प्रौद्योगिकी का एकीकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना, प्रतिभाओं को आकर्षित करना, संभावित सहयोग और गतिविधियाँ शामिल थीं।

प्रो. पूरन चंद्र पांडे ने इस बारे में भी अपना दृष्टिकोण साझा किया कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय केंद्र के लिए एक उपयुक्त स्थान क्यों है।

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अनूठा विश्वविद्यालय है, जिसे आठ सार्क देशों की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। एसएयू में लगभग आधे छात्र भारत से हैं, जबकि शेष आधे छात्र सार्क के बाकी देशों से हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) एक अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना, वित्तपोषण और रखरखाव दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के आठ सदस्य देशों की सरकारों द्वारा किया जाता है। ये देश हैं- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। एसएयू ने शैक्षणिक वर्ष 2010 से अपना संचालन शुरू किया। यह यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कानूनी अध्ययन, गणित और समाजशास्त्र सहित अध्ययन के सात क्षेत्रों में स्नातक, परास्नातक और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करती है। एसएयू पूरे दक्षिण एशिया से छात्रों को आकर्षित करता है और इसकी डिग्रियों को सभी आठ सार्क देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके कई स्नातकों को पहले ही रोजगार मिल चुका है या वे इस क्षेत्र में और दक्षिण एशिया से बाहर के देशों में आगे की पढ़ाई के लिए जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी का परिसर नई दिल्ली के मैदानगढ़ी में 100 एकड़ की हरी-भरी भूमि पर फैला हुआ है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023